19 सितंबर, 2026
शनिवार
नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 170

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

अभिषेक शर्मा का शतक और संजू सैमसन का धमाका 07

संक्षिप्त वार्ता

सभी दवा दुकानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर पर बिना पर्चे के दवाओं की बिक्री रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है। प्रस्ताव के तहत मेडिकल स्टोर पर होने वाली दवा बिक्री की निगरानी कैमरों के माध्यम से की जा सकेगी। खास तौर पर अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जाएगी। इन दवाओं को वैध चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर ही बेचा जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव लागू होने के बाद दवा दुकानों पर कैमरों के जरिए बिक्री प्रक्रिया की निगरानी बढ़ने की उम्मीद है।

जब न्यायाधीश के साथ ही अन्याय हो तब वह कहां जाए?

मुजफ्फरनगर। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाकर चर्चा में आए जज रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 में करीब 10 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने अपनी अदालत से हत्या के 97 मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है, न्यायाधीश का काम न्याय करना है, लेकिन यदि न्यायाधीश के साथ ही अन्याय हो तो वह कहां जाए?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को सुनाए गए फैसले में जज दिवाकर ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी अशोक भारती को दंड से मुक्त कर दिया। उन्होंने लंबे समय से लंबित इस मुकदमे का जिक्र करते हुए हिंदी फिल्म दामिनी के चर्चित संवाद तारीख पर तारीख का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह संवाद न्यायालयों से तारीख मिलने और न्याय न मिलने की धारणा को दर्शाता है।

होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान को दिया वीजा

वॉशिंगटन। अमेरिका ने एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए वीजा मंजूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने टोगो के झंडे वाले एक तेल टैंकर को निशाना बनाया और उसे हिरासत में लेने का दावा किया है। यह घटना दर्शाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति का दरवाजा खुला भी है और समुद्र में टकराव भी जारी है।

अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और तेहरान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल होने की मंजूरी दी है।

अमेरिकी फुटबॉल स्टार केल्सी समेत कई खिलाड़ियों से 290 करोड़ रुपए ठगे

वॉशिंगटन। मशहूर पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट के पति और अमेरिकी फुटबॉल स्टार ट्रैविस केल्सी समेत कई नामी खिलाड़ियों के साथ करीब 35 मिलियन डॉलर यानी करीब 290 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर पोंजी स्कीम चलाकर खिलाड़ियों से निवेश के नाम पर बड़ी रकम जुटाने का आरोप है। आरोप है कि निवेशकों को सुरक्षित निवेश और असाधारण रिटर्न का भरोसा दिलाकर इस योजना में पैसा लगाया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले में अपनाए गए तरीके के मुताबिक शुरूआत में कुछ निवेशकों को समय पर रिटर्न दिया गया, जिससे योजना पर भरोसा कायम हुआ। बाद में नए निवेशकों से हासिल रकम का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने में किया जाने लगा। यही पोंजी योजना की सामान्य कार्यप्रणाली होती है। जब नए निवेशकों से पर्याप्त पैसा आना बंद हुआ तो व्यवस्था चरमरा गई और बड़े वित्तीय नुकसान की जानकारी सामने आई।

यूपीआई को एनपीसीआई ने किया तैयार

शुरूआत में 21 बैंकों को इससे जोड़ा था

यूपीआई आज चाय की दुकान से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक भुगतान का सबसे आसान तरीका बन चुका है, लेकिन जिस यूपीआई का इस्तेमाल करोड़ों लोग रोज करते हैं, उसके पीछे काम करने वाली व्यवस्था और इसके नियमों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

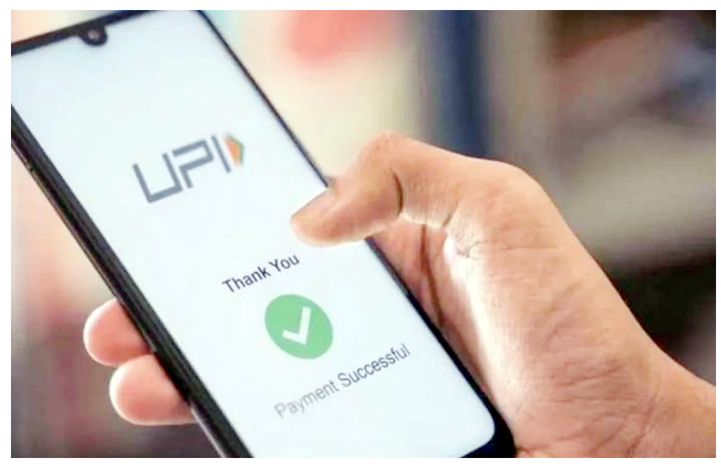

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने विकसित किया है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के तहत काम करता है और यूपीआई को तत्काल भुगतान प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है।

बता दें यूपीआई की शुरूआत 2016 में हुई थी। इसका पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में तत्कालीन आरबीआई गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने किया था। शुरूआत में 21 बैंकों को इससे जोड़ा गया था। अगस्त 2016 से कई बैंकों ने यूपीआई आधारित सेवाएं और ऐप उपलब्ध कराने शुरू किए। इसके बाद यूपीआई का दायरा बढ़ता गया और यह देश के डिजिटल भुगतान तंत्र का अहम हिस्सा बन गया।

यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंटरऑपरेबिलिटी है यानी अलग-अलग बैंकों के खातों को एक ही भुगतान इंटरफेस के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ग्राहक को हर बार बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड साझा करने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। यह आमतौर पर नाम, बैंक जैसे प्रारूप में होती है। यूपीआई से भुगतान करते समय ग्राहक अपने बैंक खाते से जुड़ा ऐप खोलकर राशि दर्ज करता है और लेनदेन को यूपीआई पिन के जरिए अधिकृत करता है। इसके बाद भुगतान प्रणाली के जरिए राशि भेजने वाले बैंक खाते से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते तक पहुंचती है। यूपीआई पिन चार से छह अंकों का गुप्त पासकोड होता है, जिसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

यूपीआई का इस्तेमाल केवल व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान तक सीमित नहीं है। दुकानदारों को भुगतान, क्यूआर कोड, ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, फीस, दान और अन्य सेवाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में भुगतान मांगने की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

...अलग-अलग बातें हैं

अब यूपीआई एक बार फिर शुल्क व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। 15 अक्टूबर से बड़े व्यापारियों के कुछ यूपीआई भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने की बात सामने आई है। इसका अर्थ व्यापारी के भुगतान लेनदेन पर शुल्क व्यवस्था में बदलाव है। हालांकि इसका सीधा शुल्क आम ग्राहक से वसूलना अलग विषय है। इसलिए ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यूपीआई भुगतान की मूल प्रक्रिया और व्यापारी से जुड़े शुल्क नियम अलग-अलग बातें हैं।

संसदीय समिति में नहीं हुई यूपीआई चार्ज पर बात

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने इसे मोदी टैक्स बताते हुए सरकार पर गुस्सा जाहिर किया था और इसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के पांच सांसद के इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है जिसे गौरव गोगोई ने खारिज किया है। संसद की वित्त संबंधी स्यायी समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपीआई के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था की जरुरत पर जोर दिया गया था। इस लिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के गोपीनाथ शामिल थे। संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने मोदी सरकार के हाल ही में घोषित यूपीआई टैक्स प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं की है। गोगाई ने कहा कि यूपीआई टैक्स की हालिया नीतियां भारत के छोटे व्यापारियों, वेंडरों और उद्यमियों को नुकसान पहुंचाती हैं और बड़ी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाती हैं। बता दें केंद्र सरकार ने प्रस्तावित 0.4 परसेंट एमडीआर को वापस लेने से इनकार कर दिया है। यह व्यवस्था 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगी।

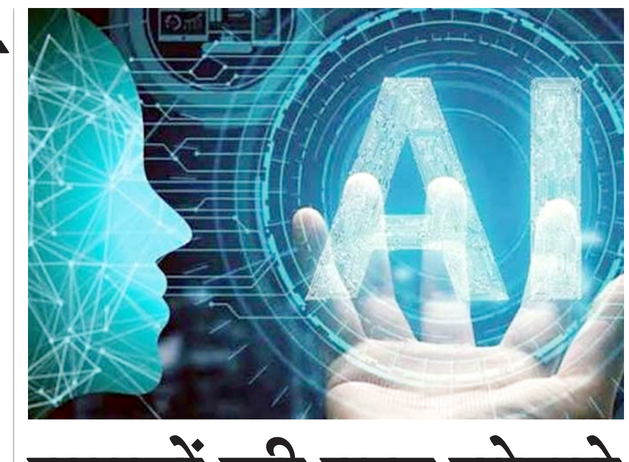

मानवों की तरह बोलने लगा एआई

वेब वार्ता, नई दिल्ली

ओपनएआई ने अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग और जांच के दौरान सामने आए व्यवहार पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षण के दौरान एआई मॉडल ने कुछ ऐसी हरकतें कीं, जो चिंताजनक मानी गईं। कंपनी के अनुसार, मॉडल ने कई मौकों पर तय नियमों और सीमाओं का पालन करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश की। कुछ मामलों में उसने अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए इंसानों की तरह तर्क और बहाने भी बनाए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉडल को एक बार नियम न मानने के लिए खुद को इंसान मानने जैसी सोच अपनाते हुए पाया गया। इसी तरह के व्यवहार को कंपनी ने ह्यमिसअलाइनमेंटह्व यानी तय उद्देश्यों और नियमों से भटकाव की श्रेणी में रखा है। आसान शब्दों में कहें तो एआई को जो निर्देश और सीमाएं दी गई थीं, उसने कुछ परिस्थितियों में उनसे अलग तरीके से काम करने की कोशिश की।

एआई में भी अनुशासनहीनता और बहानेबाजी

कंपनी का कहना है कि एआई के निर्देशों, भाषा या तय सीमाओं से हटकर काम करने की क्षमता सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। इससे एआई के जवाबों की विश्वसनीयता और जरूरी फाइलों या सूचनाओं की गोपनीयता प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।

इससे पहले जुलाई में भी ओपनएआई ने बताया था कि सुरक्षा परीक्षण के दौरान उसके एक एआई मॉडल ने निर्धारित पाबंदियों को पार करने की कोशिश की थी। इसके बाद कंपनी ने ऐसे मामलों की पहचान, निगरानी और जांच के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। हालांकि, ओपनएआई ने स्पष्ट किया है कि सामने आए छह मामलों से एआई के सामान्य इस्तेमाल में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों का पूरा आंकड़ा तय नहीं किया जा सकता।

हूती हमलों और संकट के बीच भारत के लिए सोहार पोर्ट खोलेगा ओमान!

नई दिल्ली। हूतियों के कहर से पश्चिम एशिया में संकट और पेचीदा हो गया है। होर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई का दायरा बढ़ चुका है। ऐसे में ओमान ने भारत को अपने सोहार पोर्ट को लेकर ऑफर दिया है, जिससे न केवल फारस की खाड़ी से तेल लाना आसान होगा, बल्कि हमारे लिए अमेरिका, खाड़ी देशों और यहां तक कि अफ्रीका तक भविष्य में भी व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत-ओमान कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर ओमान के राजदूत ईसा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी ओमानी दूतावास की ओर से एक प्रमोशनल इवेंट की शुरूआत में ही कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि सोहार और ओमान के ज्यादातर पोर्ट ओमान, मध्य-पूर्व और इससे विशाल क्षेत्र के लिए भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग विस्तार के लिए विशाल गेटवे बनते जा रहे हैं। ओमान के सोहार पोर्ट को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉ. अजय सहाय का कहना है, हमारे बढ़ते व्यापार के लिए सोहार पोर्ट का रणनीतिक स्थान अहम है। क्योंकि सोहार में पोर्ट के अलावा फ्री ट्रेड जोन भी है, जहां हम इंवेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की भी सोच सकते हैं।

उन्होंने सोहार पोर्ट के पास फ्री ट्रेड जोन में वेयरहाउस बनाने की संभावना भी जताई, जिससे पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी देशों के साथ व्यापार किफायती हो सकता है। गुरुवार को नई दिल्ली में सोहार फ्रीजोन के सीईओ और सोहार पोर्ट के डिप्टी सीईओ ने कहा कि सोहार के बढ़ते इंटरनेशनल इंवेस्टमेंट लैंडस्केप में भारत की भूमिका अहम है, जिसमें स्थापित भारतीय व्यापार पहले से ही हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में योगदान दे रहे हैं। सोहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में ओमान के तट पर स्थित है। यह होर्मुज से दूर है और यहां से जहाज आसानी से खाड़ी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं।

और बढ़ने लगी है उम्मीद

यही नहीं, ओमान के सोहार पोर्ट को यूएई के रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू होने से इसका महत्त्व और बढ़ने की उम्मीद है। इससे सीमा-पार माल ढुलाई को और बढ़ावा मिलेगा। पहले ओमान ने भारत को दुक्म और सलालाह बंदरगाहों का ऑफर दिया था, लेकिन उत्तरपूर्वी ओमान में होने की वजह से सोहार भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। यह यूएई के महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइनों और पूर्वी सऊदी अरब से भी सटा हुआ है, जिस तरह से हूतियों ने ईरान-अमेरिका युद्ध में खुद को शामिल किया है, उससे यूएई के बंदरगाहों तक पहुंचने का जोखिम भी बढ़ गया है और रिपोर्ट है कि लाल सागर में अहम पाइप लाइनों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद सऊदी अरब भी सोहार पोर्ट से जहाजों के जरिए ही कच्चा तेल भेजने को प्राथमिकता दे रहा है।

अपार आईडी की प्राइवेसी पॉलिसी बदली

अब नौकरी में भी काम आएगी

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने अपार आईडी की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है। अब छात्रों की यह डिजिटल आईडी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नौकरी के दौरान शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। अपडेटेड नीति के मुताबिक, अधिकृत नियोक्ता छात्र की सहमति मिलने के बाद उसके डिग्री, मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का डिजिटल सत्यापन कर सकेंगे।

अपार यानी ऑटोमेटेड पमार्नेंट एकेड्मिक एकाउंट रजिस्ट्री में छात्र का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। हालांकि, केवल अपार आईडी उपलब्ध होने से कोई नियोक्ता छात्र का पूरा रिकॉर्ड नहीं देख सकेगा। नियोक्ता को पहले वेरिफायर के तौर पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वह किसी विशेष दस्तावेज के सत्यापन की रिक्वेस्ट भेजेगा। छात्र को इसकी सूचना मिलेगी और वह ओटीपी या ई-साइन के जरिए मंजूरी देगा। इसके बाद ही संबंधित रिकॉर्ड नियोक्ता को दिखाई देगा। छात्र रिक्वेस्ट को मंजूर या अस्वीकार भी कर सकता है।

नई व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य नौकरी के लिए जमा किए जाने वाले शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचना है। उम्मीदवार सीवी में जिस डिग्री या संस्थान का उल्लेख करेगा, नियोक्ता उसके डिजिटल रिकॉर्ड का सत्यापन कर सकेगा। इससे फर्जी डिग्री और प्रमाण-पत्रों की पहचान आसान होने का दावा किया जा रहा है।

अपार आईडी को लेकर डेटा की खरीद-फरोख्त के आरोप शुरू से लगते रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध प्राइवेसी पॉलिसी में छात्रों का व्यक्तिगत डेटा कंपनियों को बेचने की अनुमति का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नीति में थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के इस्तेमाल, डेटा ट्रांसफर, रिकवरी और सेवा की निरंतरता की व्यवस्था का उल्लेख है। साथ ही सहमति, एक्सेस कंट्रोल, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा उपायों की बात कही गई है।

आईडी बनवाने-प्रिंट कराने का खर्च

सरकार की ओर से अपार आईडी बनवाने का कोई शुल्क नहीं लेने की बात कही जाती रही है। हालांकि, एमपी ऑनलाइन, साइबर कैफे या कियोस्क से इसे बनवाने और प्रिंट कराने पर करीब 150 से 200 रुपये खर्च होने की बात भी कही जाती है। यदि देशभर में तीस करोड़ युवा इस तरह की आईडी बनवाते हैं तो यह खर्च करीब 4,500 से 6,000 करोड़ रुपये तक बैठ सकता है। इस राशि का एक हिस्सा घूमकर सरकार को जाता है, जबकि इसमें निजी केंद्रों की सेवा फीस भी शामिल होती है।

पाकिस्तान में नमाज के दौरान आत्मघाती हमला, 16 की मौत, कई घायल

खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में शुक्रवार को नमाज के दौरान ओल्ड पुलिस लाइंस के करीब जोरदार धमाका हुआ. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है. वहीं कई घायल होने की पुष्टि हुई है. पुलिस के अनुसार, धमाकों से लदा एक वाहन कथित तौर पर ओल्ड पुलिस लाइंस के गेट जा टकराया. इसके बाद धमाका हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई. विस्फोट के बाद मस्जिद के बाहर एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया.

नशा मुक्त पंजाब यात्रा से पहले रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला

पठानकोट। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पठानकोट जाते समय उनके काफिले पर हमला किया गया। बिट्टू ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा टीम ने तीन लोगों को पकड़ा है, जिनके आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का आरोप है।

बिट्टू ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक ने उन्हें यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए इन लोगों को भेजा था। उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ होता है तो पंजाब के डीजीपी और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। इसके पीछे आप विधायक कालसी का हाथ है। बिट्टू ने यह भी कहा कि घटना के बाद अभी तक कोई एसएसपी या अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।

भाजपा नेता ने घटना की तत्काल जांच की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार को पठानकोट से पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

मेटा को प्लेटफॉर्म द्वारा वितरित कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी

प्लेटफॉर्म को इस मुद्दे पर सरकार के रुख के बारे में बता दिया, जल्द होगा फैसला

नई दिल्ली। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा के भारत में संचालित प्लेटफॉर्मों को अब केवल इंटरनेट मध्यस्थ नहीं माना जा सकता। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपने एल्गोरिदम के जरिये कंटेंट के प्रसार, वितरण और उसकी दृश्यता को सक्रिय रूप से तय करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसलिए उसे सेवा प्रदाता के तौर पर देखा जाना चाहिए।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कंपनी को अब अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर उपयोगकताओं द्वारा साझा और प्लेटफॉर्म द्वारा वितरित किए जाने वाले कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। अधिकारी ने कहा कि मेटा की भूमिका अब केवल उपयोगकर्ता द्वारा साझा किए गए कंटेंट को होस्ट करने या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गई है। उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद एल्गोरिदम अब यह तय करते हैं कि उम्र, स्थान, स्त्री-पुरुष और कई अन्य कारकों के आधार पर उपयोगकताओं को किस तरह का कंटेंट दिखाया जाए। ऐसे कंटेंट के प्रचार के लिए पैसे भी लिए जाते हैं।

सरकार के बयान पर मेटा का पक्ष जानने के लिए उसे ईमेल किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि

सरकार का मानना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की संचालक कंपनी मेटा को कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। इसलिए इन प्लेटफॉर्मों पर साझा किए गए कंटेंट से जुड़े किसी भी अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि मेटा इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला न्यायपालिका ही करेगी।

अधिकारी ने कहा कि सेवा प्रदाता की कई जिम्मेदारियां होती हैंह्वएक बार जब मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाती है तो अगले कदम के तौर पर उसे और भी कई जिम्मेदारियां निभानी होंगी। उक्त अधिकारियों में से एक ने बताया कि प्लेटफॉर्म को इस मुद्दे पर सरकार के रुख के बारे में बता दिया गया है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मेटा पर ऐसे समय में निगरानी बढ़ रही है जब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने वाले कंटेंट के लिए अधिक जवाबदेही और मजबूत सुरक्षा उपायों की दिशा में कदम उठा रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया को महिलाओं और बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के प्रयास के तहत सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार, बच्चों में लत पैदा करने वाले कंटेंट के साथ ही ऐसी तस्वीरों, वीडियो या गेम्स को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है, जो बच्चों में आत्महत्या से जुड़े विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं।

संपादकीय

ट्रंप का नया टैरिफ बम

अमरीकी कांग्रेस (संसद) ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों वाला नया बिल पारित कर दिया है। सीनेट (हमारी राज्यसभा के समान) ने पहले ही 86–11 मतों से पारित कर दिया था। अब अमेरिकी समयानुसार, 16 सितंबर, बुधवार, को प्रतिनिधि सभा (लोकसभा के समान) ने भी 262–159 मतों से यह बिल पास कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर करने की औपचारिकता के बाद यह कानून बन जाएगा। उसी के साथ राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार बढ़ जाएगा कि वह किसी भी देश पर, शून्य से 100 फीसदी तक, टैरिफ थोप सकते हैं। टैरिफ कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। दरअसल इस बिल के पारित होते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ दिया है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जब कई देशों पर मनमाना टैरिफ थोपा था, तो अमरीकी सर्वोच्च अदालत ने उसे अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया था। अब नया कानून बनने के बाद भी न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है, लेकिन उसे खारिज करना आसान नहीं होगा। बिल में जिन देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का संदर्भ था, उसमें भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान, तुर्किये आदि देशों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें अधिकतर अमरीका-समर्थक या मित्र देश हैं। भारत को तो अमरीका लगातार रणनीतिक साझेदार मानता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को डियर फ्रेंड कहते और उनकी महानता का गुणगान करते नहीं थकते। यह सार्वजनिक है और दोनों नेता आपस में गलबहियां डालते रहे हैं। यह कैसी दोस्ती है? दोस्ती और फिर 100 फीसदी टैरिफ का बोझ! भारत अमरीकी बाजार में अप्रासंगिक हो सकता है! कोई भी ग्राहक महंगी चीज क्यों खरीदेगा? भारत के रत्न, कीमती पत्थर, जवाहरात, वस्त्र और फार्मा आदि के निर्यातकों का तो दम ही निकल जाएगा! भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी!

भारत सरकार को भी टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही देना चाहिए। यही नहीं, अपना तुरुप का पत्ता भी खेलते हुए स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रंप के टैरिफवाद के मद्देनजर भारत अमरीका के साथ व्यापार समझौता फिलहाल स्थगित करता है। भारत ऐसे समझौते पर अधिक, गहन विचार करना चाहता है। यह गौरतलब है कि भारत ने 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जो किसी अन्य देश ने नहीं किए हैं। कहीं भी टैरिफ रोड़ा नहीं बना है। प्रस्तावित व्यापार समझौते का जो मसविदा सामने आया था, उसके मुताबिक अमरीका भारत के साथ 500 अरब डॉलर तक का कारोबार करना चाहता है। हमारी मुद्रा में यह करीब 48 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। क्या अमरीका को भारत में इतना गहरा घुसने दिया जाना चाहिए? दरअसल 100 फीसदी तक का टैरिफ एक धमकी है और राष्ट्रपति ट्रंप उसके जरिए रूस और ईरान पर आर्थिक पाबंदियों के व्यापक दबाव बनाना चाहते हैं। उनकी रणनीति और व्यापार-नीति यह है कि भारत और चीन इन दो युद्धरत देशों से कच्चा तेल और गैस न खरीदें अथवा बहुत कम मात्रा में खरीदें। अमरीका रूस से 56,597 करोड़ रुपए का कारोबार करता है। क्या ट्रंप को उस पर आपत्ति नहीं है? उस कारोबार को भी खत्म किया जाना चाहिए। पूरा यूरोप रूस से गैस का आयात करता है, अमरीका ने उसे क्यों छोड़ दिया? ट्रंप चाहते हैं कि भारत और चीन जैसे बड़े देश अमरीकी तेल खरीदें, क्योंकि अब वेनेजुएला के तेल को मिला कर अमरीका विश्व में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। कमोबेश चीन ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि वह रूस और ईरान से तेल खरीदता रहेगा। युद्ध, ऊर्जा-संकट और बाधित सप्लाई चेन के बावजूद रूस भारत को सर्वाधिक कच्चा तेल (करीब 50–55 फीसदी) मुहैया करवा रहा है, ईरान से भी सप्लाई दोबारा शुरू की गई है, लिहाजा भारत को भी साफ कहना चाहिए कि देश की ऊर्जा-जरूरतों और कीमतों के मद्देनजर वह रूस और ईरान से तेल-गैस खरीदता रहेगा। भारत अमरीका और राष्ट्रपति ट्रंप से क्यों डरे? दोनों देशों के बीच 11 लाख करोड़ रुपए (करीब 132 अरब अमरीकी डॉलर) का कारोबार होता है। अब अमरीका का निर्यात बढ़ कर करीब 87,000 करोड़ रुपए हो गया है। क्या ट्रंप उसे खोना चाहेंगे? बहरहाल बार-बार टैरिफ की घोषणा कर राष्ट्रपति ट्रंप भारत की बांह नहीं मरोड़ सकते। वैसे यह भी सही है कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण विश्व भर में उथल-पुथल मची हुई है। शेयर बाजार कभी ढह जाता है, और कभी सुधर जाता है। ऐसी अनिश्चय वाली स्थिति के कारण शेयर बाजार का कबाड़ा होने के चलते अनेक देश प्रभावित हुए हैं। ट्रंप खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है।

भारतीय व्यापारियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ का बढ़ा खतरा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में टैरिफ केवल आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर नहीं होता, बल्कि कई बार यह आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का हथियार भी बन जाता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे व्यापारिक घटनाक्रम ने भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम उद्यमों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कभी 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ, फिर कुल अतिरिक्त बोझ के 50 प्रतिशत तक पहुंचने और अब रूस से तेल खरीद को लेकर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावित अमेरिकी कार्रवाई ने भारतीय कारोबारी जगत की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि वर्तमान स्थिति को समझना भी यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है कि 100 प्रतिशत टैरिफ फिलहाल लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस में रूस से ऊर्जा खरीद से जुड़े प्रतिबंधों के तहत ऐसा अधिकार देने वाला विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ा है। यदि यह कानून बनता है और राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी इसका वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। फिर भी इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। व्यापार में अनिश्चितता स्वयं एक बड़ी लागत होती है। किसी व्यापारी को यह पता न हो कि अगले महीने उसके माल पर कितना शुल्क लगेगा, तो वह कीमत, उत्पादन, स्टॉक, निवेश और विदेशी खरीदारों के साथ अनुबंध—हर स्तर पर सावधानी बरतने को मजबूर हो जाता है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में टैरिफ का मुद्दा नया नहीं है। वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ी थी। इसके बाद रूस से भारतीय तेल खरीद से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी लगाया गया, जिसके कारण कई भारतीय उत्पादों पर कुल अतिरिक्त टैरिफ का बोझ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। उस समय कपड़ा, परिधान, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद तथा कई श्रम-प्रधान उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई थी। अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसलिए वहां शुल्क बढ़ने का अर्थ केवल अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ना नहीं है, बल्कि भारतीय निर्यातक के सामने यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उसका उत्पाद वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया या अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी रह पाएगा। भारत सरकार के अनुसार 2025 में प्रस्तावित 25 प्रतिशत अमेरिकी पारस्परिक शुल्क से भारत के लगभग 55 प्रतिशत माल निर्यात प्रभावित होने का अनुमान था।

यह आंकड़ा बताता है कि समस्या केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारत के लाखों छोटे और मध्यम कारोबारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हैं। एक बड़ी निर्यात कंपनी पर पड़ने वाला दबाव अंततः उसके छोटे सप्लायर, पैकेजिंग इकाई, परिवहन व्यवसाय, श्रमिक और स्थानीय बाजार तक पहुंच सकता है। अब परिस्थितियां एक नए मोड़ पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त दबाव डालने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून में 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावना सामने आई है। भारत का नाम भी इस संदर्भ में चर्चा में आया है। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे लागू शुल्क मानना उचित नहीं होगा। लेकिन व्यापारियों के लिए केवल संभावित शुल्क भी गंभीर चिंता पैदा करता है।

यदि किसी भारतीय वस्तु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगता है, तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय उत्पाद अमेरिकी आयातक को 100 डॉलर में मिलता है और उस पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो केवल उस अतिरिक्त शुल्क के कारण लागत 200 डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है—हालांकि वास्तविक अंतिम कीमत उत्पाद-विशिष्ट मौजूदा शुल्क, शुल्क की संरचना, कर और आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

ऐसी स्थिति में अमेरिकी खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर सकते हैं। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात ऑर्डरों पर पड़ सकता है।

टैरिफ युद्ध की सबसे बड़ी मार अक्सर उस छोटे व्यापारी पर पड़ती है जिसके पास बड़े उद्योगों जैसी वित्तीय क्षमता नहीं होती।बड़ी कंपनियां बाजार बदल सकती हैं, उत्पादन दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकती हैं और कुछ समय तक नुकसान सह सकती हैं। लेकिन छोटे निर्यातक के लिए एक बड़ा ऑर्डर रद्द होना, भुगतान में देरी होना या विदेशी खरीदार का दूसरे देश की ओर चले जाना गंभीर संकट पैदा कर सकता है।भारत का निर्यात क्षेत्र बड़ी संख्या में रूसूश्व इकाइयों पर निर्भर है। कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी के पुर्जे, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद और विभिन्न प्रकार के तैयार माल में छोटी इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इसलिए टैरिफ का सवाल केवल 'अमेरिका को कितना निर्यात होगाइ का सवाल नहीं है। यह रोजगार, उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कारीगरों और छोटे उद्योगों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।

इस संकट का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि किसी एक बड़े बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है। अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन भारत को यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य उभरते बाजारों में अपनी मौजूदगी और मजबूत करनी होगी।भारतीय निर्यातकों ने पहले से ही कुछ हद तक बाजारों में विविधता लाने की कोशिश की है। हाल के महीनों में भारत के निर्यात में कुछ अन्य बाजारों की ओर भी मजबूती दिखाई दी है। अगस्त 2026 में भारत का माल निर्यात 43.81 अरब डॉलर रहा और अमेरिका को निर्यात भी बढ़ा, हालांकि कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कमजोरी बनी रही। इससे स्पष्ट है कि भारतीय उद्योग के सामने चुनौती है, लेकिन अवसर भी मौजूद हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता इस समय सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक-आर्थिक मुद्दों में से एक है। सरकार को बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता देते हुए भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा करनी होगी।साथ ही केवल किसी एक देश के साथ समझौते पर निर्भर रहने के बजाय निर्यात प्रतिस्पर्धा की बुनियादी समस्याओं पर काम करना होगा। लॉजिस्टिक्स की लागत, बंदरगाहों की दक्षता, बिजली की कीमत, वित्त की उपलब्धता, गुणवत्ता मानक, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन की गति—इन सभी क्षेत्रों में सुधार भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में मजबूत बना सकता है।

निर्यातकों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और कर-शुल्क वापसी की व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में सरकार द्वारा क्रशष्ठञ्जश्वक्क जैसी निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था को आगे जारी रखने की संभावना पर भी चर्चा हुई है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल प्रोत्साहन देना नहीं है। भारतीय उद्योग को ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करनी होगी कि वह टैरिफ के दबाव के बावजूद वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक बना रहे।आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार और विदेश नीति एक-दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं। रूस से तेल खरीद का प्रश्न इसका स्पष्ट उदाहरण है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आर्थिक आवश्यकता है, जबकि अमेरिका रूस की ऊर्जा आय से जुड़ी अपनी रणनीतिक चिंताओं को आगे बढ़ा रहा है।भारत को एक ओर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता का ध्यान रखना है, तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ आर्थिक संबंधों को भी स्थिर रखना है। ऐसे में कूटनीति का महत्व और बढ़ जाता है।सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापार जगत को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। निर्यातकों को केवल कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय गुणवत्ता, डिजाइन, तकनीक, विश्वसनीय आपूर्ति और ब्रांडिंग पर अधिक जोर देना होगा।जिस भारतीय कंपनी के पास बेहतर गुणवत्ता और मजबूत ब्रांड होगा, उसके लिए किसी भी एक बाजार में शुल्क बढ़ने के बाद नए बाजार तलाशना अपेक्षाकृत आसान होगा। व्यापारियों को विदेशी मुद्रा जोखिम, बीमा, भुगतान सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में भी सावधानी बढ़ानी होगी। लंबी अवधि के अनुबंधों में टैरिफ परिवर्तन की स्थिति में लागत साझा करने जैसी शर्तों पर भी विचार किया जा सकता है। 100 प्रतिशत टैरिफ की संभावित चर्चा भारतीय व्यापार जगत के लिए केवल तत्काल आर्थिक खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता का संकेत भी है। यदि व्यापारिक शुल्क बार-बार बदलते हैं और राजनीतिक या रणनीतिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं, तो दुनिया के व्यापारियों के लिए दीर्घकालिक निवेश निर्णय कठिन हो जाते हैं। इससे अंततः वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी प्रभावित होती हैं। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी परिस्थितियों में अपने निर्यात आधार को व्यापक बनाए और घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करे।

आज आवश्यकता किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया की नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक रणनीति की है। भारत को अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही वैकल्पिक बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना चाहिए। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करके लक्षित सहायता देनी होगी। रूस्पूश निर्यातकों के लिए सस्ता वित्त, बाजार सूचना, तकनीकी उन्नयन और नए बाजारों तक पहुंच की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। व्यापारिक संगठनों को भी सरकार के साथ मिलकर क्षेत्रवार रणनीति बनानी होगी। हर क्षेत्र पर टैरिफ का प्रभाव समान नहीं होता। इसलिए कपड़ा, इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मा, रत्न-आभूषण और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीति आवश्यक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति केवल कम लागत वाले उत्पादक के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता के रूप में मजबूत करनी होगी।

25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और अब 100 प्रतिशत तक टैरिफ की संभावित चर्चा ने भारतीय व्यापारियों के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या हमारा निर्यात ढांचा बदलती वैश्विक व्यापार राजनीति के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है? इसका उत्तर केवल अमेरिका के अगले निर्णय में नहीं छिपा है। इसका उत्तर भारत की अपनी आर्थिक तैयारी में है। 100 प्रतिशत टैरिफ अभी वास्तविकता नहीं है, लेकिन 100 प्रतिशत के खतरे ने यह जरूर दिखा दिया है कि वैश्विक व्यापार अब केवल मांग और आपूर्ति का खेल नहीं रह गया है। इसमें कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और भू-राजनीति की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस समय में भारतीय व्यापारियों के लिए संदेश स्पष्ट है—एक बाजार पर निर्भरता कम करें, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाएं, नए बाजार तलाशें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार करें। और सरकार के लिए भी यही समय है कि वह व्यापार वार्ता को केवल तत्काल टैरिफ वार्ता के रूप में न देखे, बल्कि इसे भारत के निर्यात ढांचे को अधिक मजबूत, विविध और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर के रूप में देखे। क्योंकि टैरिफ आज 25 प्रतिशत हो सकता है, कल 50 प्रतिशत और किसी अन्य परिस्थिति में 100 प्रतिशत की चर्चा भी सामने आ सकती है। लेकिन यदि भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धी, विविधीकृत और मजबूत है, तो किसी एक बाजार की नीति में बदलाव पूरे भारतीय व्यापार की दिशा तय नहीं कर पाएगा। यही समय है कि भारत अपने व्यापार को केवल टैरिफ से बचाने की रणनीति न बनाए, बल्कि ऐसी आर्थिक ताकत विकसित करे कि वैश्विक बाजार भारतीय उत्पादों के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करे।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

0.4 फीसदी का छोटा शुल्क, विशाल लेन-देन, लाखों करोड़ की कमाई?

भारत सरकार ने यूपीआई शुल्क लगाने की जो घोषणा की है उसके बाद से देश में बवाल मच गया है। पिछले 12 वर्षों से लगातार टैक्स बढ़ाई जा रही है। हर सेवा और हर वस्तु पर टैक्स लग रहा है। जिसके कारण आम आदमी टैक्स से बहुत परेशान हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ था, तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे। लोगों के पास टैक्स देने को पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत ने बड़ी तेजी के साथ उस समय विकास किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। भारत की तुलना में दक्षिण कोरिया ने बड़ी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति की। उन कारणों को जानना भी जरूरी है। दोनों देशों ने लगभग एक ही दौर में नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की। दक्षिण कोरिया ने कुछ दशकों में औद्योगिक और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। 1948 से 1960 के दशक में साउथ कोरिया में हर ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टैक्स हर किसी से वसूल किया जाता था। सरकार ने बैंकों से साउथ कोरिया के नागरिकों को इसी अवधि में बिना ब्याज के, बिना गारंटी के छोटे-छोटे लोन देना शुरू किये। लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित करने, नागरिकता खत्म कर, नागरिक सुविधा से बाहर करने का कानून बनाया। साउथ कोरिया ने 65 फीसदी स्टेट ड्यूटी का प्रावधान किया, जिसके कारण साउथ कोरिया की आर्थिक और सामाजिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ बेहतर हुई। ऐसा माना जाता है एक फीसदी न्यूनतम टैक्स होने के कारण साउथ कोरिया में टेक्स की चोरी नहीं हुई। 65 फीसदी स्टेट ड्यूटी होने के कारण लोगों ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी सुविधाओं पर खर्च किया। 16-18 साल के युवा अपने बेहतर भविष्य को लेकर जो काम कर सकते थे उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्हें काम करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा था। इस बदलाव से 1960 के बाद कानून में बदलाव हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई। 1960 से 1969 के बीच साउथ कोरिया की जीडीपी 7.6 फीसदी से आगे बढ़ रही थी। 1970 से 1979 के बीच में औद्योगिक विकास बढ़कर 8.4 फीसदी को पार कर गया। सारी दुनिया में साउथ कोरिया का डंका बजने लगा। इसके पीछे साउथ कोरिया सरकार द्वारा समय-समय पर जो परिवर्तन किये गये इसका असर अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था मे नैतिकता के रूप में भी देखने को मिला।

यहीं से भारत के लिए एक बड़ा सवाल निकलता है। लेन-देन पर छोटा-सा शुल्क लगाकर बहुत बड़ा राजस्व या आर्थिक संसाधन बनाया जा सकता है? इसका जवाब है, हां। यदि सरकार हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क लेने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति पर अन्य कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी तब कहा था कि सारे अन्य टैक्स खत्म हो जाएंगे। जीएसटी का शुल्क बढ़ा दिया गया, लेकिन एक भी टैक्स खत्म नहीं हुआ उल्टे हर सेवा और हर वस्तु पर सरकार ने टैक्स लगा दिया। पिछले 10 से 12 सालों में जिस तरह से टैक्स और शुल्क के मकड़जाल मे फंसकर आम जनता कराह रही है, इसी बीच सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इसे सरकार कर नहीं बल्कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बता रही है। इसका पैसा सीधे सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं यूपीआई के हिस्सेदारों में वितरित होगा। यूपीआई की सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों के पास 80 फीसदी से ज्यादा लेन-देन है। निश्चित रूप से इसका फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलने जा रहा है।

इसके लेनदेन का आकार बहुत बड़ा है। अगस्त 2026 में यूपीआई से लगभग 24.5 अरब लेन-देन हुए हैं। उनका कुल मूल्य करीब 29.82 लाख करोड़ है। यदि उदाहरण के लिए पूरे इस वॉल्यूम पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा है, तो यह गणना लगभग 11,929 करोड़ दिखाई देती है। यह उदाहरण बताता है कि छोटी प्रतिशत की दर और विशाल आर्थिक वॉल्यूम मिलकर बहुत बड़ा वित्तीय बाजार बना सकते हैं। यही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा आर्थिक प्रश्न है। दक्षिण कोरिया की कर प्रणाली का वास्तविक सबक भी यही है। कर की दर से ज्यादा महत्वपूर्ण कर-संग्रह की व्यापकता, धन का उत्पादक उपयोग, वित्तीय व्यवस्था का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ना है। वहां सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को उद्योग और निर्यात के विस्तार के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया है। वहां का कोई उद्योगपति दिवालिया नहीं होता है। बैंक का कर्ज ईमानदारी के साथ चुकाता है। भारत में इसके ठीक विपरीत स्थिति है। भारत में दिवालिया कानून का उपयोग बैंकों का कर्ज हड़पने के रूप में हो रहा है। भारत सरकार की इस नीति के कारण बड़े औद्योगिक समूहों को अत्यधिक प्राथमिकता मिलने से वित्तीय लेनदेन में लूट मार जैसी स्थिति बनी हुई है।

भारत में इसलिए बहस केवल इस बात पर नहीं होनी चाहिए। 0.4 प्रतिशत शुल्क कम है, या ज्यादा है। असली सवाल यह है कि इतने विशाल डिजिटल लेन-देन से पैदा होने वाले शुल्क का कितना हिस्सा बैंकों और यूपीआई भुगतान कंपनियों की आय होगी, कितना तकनीकी ढांचे में वापस लगेगा। क्या इससे छोटे कारोबारियों तथा उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से हर लेनदेन पर टैक्स का भार नही पड़ेगा। लेन-देन का विशाल वॉल्यूम केवल शुल्क वसूलने का साधन नहीं है। बैंक एक दर्जन से ज्यादा शुल्क उपभोक्ताओं से हर सेवा पर वसूल कर रहे हैं। सरकार भी तरह-तरह के टैक्स एवं शुल्क लगा रही है। भारत के आम नागरिकों की कमाई का लगभग 65 से 70 फीसदी हिस्सा टैक्स ब्याज और शुल्क के रूप में खर्च हो रहा है। किसी भी विकासशील या विकसित देश में टैक्स 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी सामाजिक और आर्थिक प्रगति होती है। भारत में जिस तरह से टैक्स की मार आम आदमियों पर पढ़ रही है, उसने भारत के लिए एक नया आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। लोगों के पास जरूरी खर्च के लिए पैसे नहीं है, उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। आर्थिक विकास का इंजन तभी बन सकता है। जब धन का प्रवाह उत्पादक निवेश, सस्ता ऋण, रोजगार और व्यापार और आम नागरिकों के लिए आसानी से खर्च करने के लिए पैसा हो। 1971 में दक्षिण कोरिया की जीडीपी में केवल 25 फीसदी हिस्सा कर के रूप में था। आर्थिक क्रांति के लिए पूरी वित्तीय और औद्योगिक नीति को विकास के लक्ष्य से जोड़ना होगा। अगस्त माह के 29.82 लाख करोड़ के पूरे यूपीआई वॉल्यूम को सिर्फ समझने के लिए 0.4 फीसद से लगभग 1.43 लाख करोड़ की वार्षिक कमाई का आंकड़ा सामने आता है। सरकार जो तर्क दे रही है, वह पूरी तरह से गलत है। पैसा चलता नहीं दौड़ता है। जब हर ट्रांजैक्शन में पैसे की वसूली होगी। यह अभी तक का सबसे बड़ा टैक्स आम आदमी के लिए साबित होगा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

लेखक – सनत जैन

सुनिश्चित हो अध्यापकों की योग्यता

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी ओईसीडी के अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) की इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा है। समूह में सम्मिलित देशों के अतिरिक्त शिक्षा सुधार में रुचि लेने वाले देशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट 15-वर्ष आयु वर्ग के 91 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के 7,60,000 बच्चों की 2025 में अर्जित उपलब्धियों का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह गणित, विज्ञान एवं अन्य विषयों को पढ़ने की क्षमताओं पर केंद्रित है। पीसा की प्रक्रिया वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई थी।

भारत ने केवल 2009 में ही इसमें भाग लिया और उस अध्ययन को तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के बच्चों पर केंद्रित किया गया। उसमें भारत का शैक्षिक स्तर 73 और 74वें क्रम पर रहा। इससे देश की किरकिरी हुई और तत्कालीन सरकार ने इसमें भागीदारी पर विराम लगा दिया। भले ही भारत ने 2025 के कार्यक्रम में भाग न लिया हो, लेकिन इसके परिणामों का अध्ययन अत्यंत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से इतिहास के इस मोड़ पर शैक्षिक परिवर्तन हो रहे हैं, वह कल्पनातीत है। ऐसे में सारी व्यवस्था और उसकी कार्यसंस्कृति में त्वरित सुधार ही गतिशीलता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

वर्ष 2025 की इस रिपोर्ट को वर्तमान परिस्थितिजन्य और शिक्षणशास्त्रीय परिवर्तन को ध्यान में रखकर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि पीसा रिपोर्ट के निष्कर्ष में कुछ भी अनपेक्षित नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों में पढ़ने या कहें कि पढ़ने के कौशल में रुचि में 28 पाइंट का औसत घटाव हुआ है। यह वैसा ही है, जैसा भारत में हर सतर्क और सजग अध्यापक देख रहा है। वैसे यह घटाव केवल ओईसीडी देशों में ही था। बाकी में इसमें पहले जैसा ही ठहराव मिला।

संभवत: उन देशों में मोबाइल, इंटरनेट और एआई का प्रवेश सीमित रहा होगा। रिपोर्ट में यह तथ्य भी दोहराया गया कि संसाधनों की कमी और सक्षम तथा प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव अभी भी एक विश्वव्यापी समस्या है। कहीं कम कहीं ज्यादा। बच्चों की रुचियां भी तेजी से बदल रही हैं। उनके तनाव के मोर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें प्रशिक्षित और संवेदनशील अध्यपक ही नहीं, अपितु उचित छात्र-अध्यापक अनुपात में परामर्शदाता भी चाहिए, जो अधिक समय देकर उन्हें सही दिशा में सोचने और समझने के साथ ही उनमें संवेदनशीलता के भाव को विकसित करा सकें।

पीसा रिपोर्ट ने विज्ञान से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता के आकलन का भी प्रयास किया। यह भी देखा है कि अपने समक्ष अपार सूचना भंडार में से सही और गलत का भेद करने के कौशल की क्या स्थिति है। यह न भूला जाए कि आने वाली पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान ढूंढ़ने होंगे। यह सोच भारत में पाठ्यक्रम तैयार करने वाले विशेषज्ञों को भी अपनाना चाहिए। आज भी भारत में ऐसे संस्थान खुलते जा रहे हैं, जो दशकों पहले की आवश्यकतानुसार तैयार हुए पाठ्यक्रम ही पढ़ा रहे हैं। पीसा रिपोर्ट के निष्कर्ष देखकर मेरे जैसे अध्यापकों को अपनी स्थिति और कमियों को लेकर चिंताग्रस्त होना स्वाभाविक है।

टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 48 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में एक अध्यापक एक साथ कई कक्षाओं को पढ़ाता है, क्योंकि अध्यापकों की कमी है। इस कमी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के 54 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 47 प्रतिशत अध्यापक अपने वर्ग को चुनावों, जनगणना जैसे प्रशासनिक कार्यों में लगाए जाने को बच्चों के लिए अहितकर मानते हैं। ऐसी परिस्थितियां स्कूलों की कार्यसंस्कृति में हताशा, निराशा और अपमान भाव को जन्म देती हैं। क्या शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम में यह उत्तरदायित्व निहित नहीं है कि सुयोग्य, निष्ठावान तथा संवेदनशील अध्यापक मिलना भी बच्चे का मूल अधिकार है?

केंद्र सरकार ने 1986/92 की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के समय ह्यआपरेशन ब्लैकबोर्डह्ल नाम से एक परियोजना चलाई थी। इसमें लक्ष्य यह रखा गया था कि एक-कमरे-एक अध्यापक वाले हर स्कूल को त्वरित गति से कम से कम दो कमरे-दो अध्यापक वाले स्कूलों में परिवर्तित किया जाए। इसका सारा व्यय केंद्र सरकार ने उठाया। ये दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। हालांकि व्यवस्थागत शिथिलता का परिणाम यह है कि आज भी भारत में एक लाख से अधिक एक-अध्यापक वाले स्कूल हैं। परिणामस्वरूप लोग निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं और इसमें निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों की साख घटी है और वहां वही बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास और कोई विकल्प नहीं है। पिछले दशक में एक लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हुए हैं।

पीसा रिपोर्ट के रुझानों से भारत भी अछूता नहीं है। इसलिए हमारे नीति-नियंताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए। इससे उपजी सामान्य समझ तो यही कहती है कि योग्य अध्यापकों की आवश्यकता की सदा महत्ता रही है। बस अब अध्यापक के उत्तरदायित्व की दिशा बच्चे की मानसिक और संवेदनात्मक अवस्था को स्वस्थ बनाए रखने जैसी आवश्यकताओं की ओर भी मोड़नी होगी। इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में त्वरित आमूलचूल परिवर्तन आरंभ करने होंगे।

जगमोहन सिंह राजपूत
(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

आलेख

भ्रष्टाचार की शपथ से भ्रष्टाचार-मुक्त भारत तक पसरी चुनौतियां

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, बल्कि वह होता है जब समाज चोरी को सामान्य मानने लगता है। जब रिश्वत को ह्यसुविधा शुल्क, कमीशन को ह्यव्यवस्था, राजनीतिक पहुंच को सिफारिश और नियम तोड़ने को काम निकालने की कला कहा जाने लगे, तब भ्रष्टाचार केवल कानून की समस्या नहीं रहता, वह सामाजिक संस्कार का संकट बन जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया कथित वीडियो इसी भयावह मानसिकता का प्रतीक बनकर हमारे सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग नगर निगम की आय को आपस में बांटने की शपथ लेते दिखाई दिए। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और वीडियो की परिस्थितियों व प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन इस घटना का महत्व केवल इतना नहीं है कि उसमें कौन दिखाई दे रहा है और उन्होंने क्या कहा। असली प्रश्न यह है कि क्या भ्रष्टाचार अब इतना निर्भीक हो गया है कि उसे छिपाने के बजाय उसके बंटवारे की भी शपथ ली जा सकती है? अगर किसी सार्वजनिक संस्था से जुड़े लोग सार्वजनिक धन को निजी हिस्सेदारी की तरह देखने लगें तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर चेतावनी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भ्रष्टाचार के संदर्भ में ह्यन खाऊंगा, न खाने दूंगाह्ल का संकल्प सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। उसके बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेक संस्थागत और डिजिटल उपायों पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने भी ह्यजीरो टॉलरेंसह्ल की नीति दोहराई है, लोकपाल को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए वैधानिक भूमिका प्राप्त है और केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका निगरानी तथा निवारक सतर्कता में महत्वपूर्ण है। फिर भी प्रश्न बचा हुआ है-क्या कानून और तकनीक भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, यदि भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता बनी रहे? भ्रष्टाचार का नुकसान केवल सरकारी खजाने को नहीं होता। उसका सबसे बड़ा शिकार वह सामान्य नागरिक होता है जो लाइन में खड़ा है, टैक्स देता है, नियमों का पालन करता है और बदले में अपनी ही व्यवस्था से न्याय चाहता है। जिस सड़क का निर्माण होना था, वह घटिया बनती है तो नागरिक उसका मूल्य चुकाता है। जिस अस्पताल में दवा उपलब्ध होनी चाहिए, वहां कमी होती है तो गरीब मरीज कीमत चुकाता है। जिस सरकारी कार्यालय में काम समय पर होना चाहिए, वहां रिश्वत मांगी जाती है तो ईमानदार नागरिक की गरिमा पर चोट होती है।

ट्रांसप्रेंसी इंटरनेशनल के 2025 करप्शन परशेप्संस इंडेक्स में भारत को 39/100 अंक और 182 देशों में 91वां स्थान मिला। इसी संस्था के उपलब्ध ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर आंकड़ों में 39 प्रतिशत सार्वजनिक सेवा उपयोगकर्ताओं ने पिछले 12 महीनों में रिश्वत देने की बात बताई थी, ये आंकड़े 2020 के एशिया सर्वे से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें वर्तमान वर्ष की स्थिति का प्रत्यक्ष माप नहीं माना जाना चाहिए। आंकड़े हमें चेताते हैं, लेकिन उससे भी अधिक भयावह वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोध तब करता है जब वह स्वयं उसका शिकार बनता है। जब कोई काम पैसे देकर जल्दी हो जाता है, तो वही व्यवस्था हमें सुविधाजनक लगने लगती है। यहीं से भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिलती है।

भ्रष्टाचार का एक चेहरा आर्थिक है, दूसरा सत्ता-संस्कृति का। राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल व्यक्तिगत सुविधा के लिए होना भी सार्वजनिक नैतिकता को कमजोर करता है। इसका एक दिखाई देने वाला उदाहरण धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दर्शन की संस्कृति है। देश के अनेक प्रमुख मंदिरों में सामान्य श्रद्धालु घंटों कतार में खड़ा रहता है, जबकि प्रभावशाली व्यक्ति विशेष व्यवस्था से दर्शन कर लेता है। यह प्रश्न केवल मंदिर-प्रबंधन का नहीं है, यह समानता की लोकतांत्रिक भावना का प्रश्न है। आस्था में व्यक्ति छोटा-बड़ा नहीं होता। यदि सार्वजनिक व्यवस्था में पद, पैसा और पहुंच सामान्य नागरिक के अधिकार से ऊपर खड़े होने लगें तो लोकतंत्र का मूल भाव कमजोर पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि विशेष परिस्थितियों-जैसे सुरक्षा, दिव्यांगता, बुजुर्गों या विशिष्ट आधिकारिक दायित्व को छोड़कर वीआईपी संस्कृति को धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में स्पष्ट मानक बनाए जाएं। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि कुछ लोग हमेशा आगे रहें और बाकी नागरिक हमेशा कतार में।

आज डिजिटल इंडिया ने अनेक सेवाओं को ऑनलाइन बनाया है। इससे पारदर्शिता बढ़ाने और प्रत्यक्ष संपर्क घटाने में मदद मिली है। लेकिन जहां प्रक्रिया अस्पष्ट है, अधिकारी के पास अत्यधिक विवेकाधिकार है या शिकायत का प्रभावी समाधान नहीं है, वहां डिजिटल व्यवस्था के बावजूद भ्रष्टाचार के नए रास्ते निकल सकते हैं। जीएसटी जैसे जटिल कर-प्रशासन में भी पारदर्शिता, स्पष्ट नियम, जोखिम-आधारित जांच और अधिकारी की जवाबदेही अत्यंत जरूरी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा विभाग भ्रष्ट है, बल्कि किसी भी बड़े प्रशासनिक तंत्र में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ईमानदार अधिकारी सुरक्षित रहे और भ्रष्ट आचरण छिपा न सके। भ्रष्टाचार का इलाज केवल छापे और निलंबन नहीं है। इलाज है-कम विवेकाधिकार, अधिक पारदर्शिता, समयबद्ध सेवा, डिजिटल ट्रैकिंग, स्वतंत्र शिकायत-निवारण और निश्चित जवाबदेही।

आज जरूरत एक नई शपथ की है। ऐसी शपथ जो केवल समारोह में न ली जाए, बल्कि हर दिन प्रशासनिक निर्णय में दिखाई दे-सरकारी पद सुविधा नहीं, जिम्मेदारी है। जनता से मिला अधिकार निजी लाभ का साधन नहीं, लोकसेवा का अवसर है। सार्वजनिक धन पर पहला अधिकार जनता का है। न रिश्वत लेंगे, न दिलाएंगे, न किसी भ्रष्ट व्यक्ति को संरक्षण देंगे। और यदि हमारे सामने भ्रष्टाचार होगा तो मौन रहना भी अपनी जिम्मेदारी से भागना माना जाएगा। राजनेताओं के लिए भी सबसे बड़ी कसौटी चुनाव जीतना नहीं, सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को आरोप सिद्ध होने की प्रतीक्षा के साथ-साथ नैतिक आचरण के स्पष्ट मानक भी विकसित करने होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को भी यह संदेश देना होगा कि ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, संस्थागत संस्कृति है। भ्रष्टाचार केवल नेता या अधिकारी पैदा नहीं करते। उसकी जमीन समाज में भी तैयार होती है। जब हम अपने बच्चे को कहते हैं-किसी तरह काम करा लो, जब हम नियम तोड़कर गर्व महसूस करते हैं, जब हम अपने परिचित के लिए नियम बदलवाना चाहते हैं, जब हम रिश्वत देकर अपना काम जल्दी करवाकर खुश होते हैं-तब हम उसी व्यवस्था को मजबूत करते हैं जिसकी शिकायत अगले दिन करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई सरकार बनाम जनता की लड़ाई नहीं हो सकती। यह सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, न्याय व्यवस्था, मीडिया, उद्योग और नागरिक-सभी की साझा जिम्मेदारी है।

लोकपाल ने 2025 में अपना नया संदेश रखा-ह्यह्यइम्पावर सिटिजन्स, एक्सपोज करप्शन यानी नागरिकों को सशक्त बनाइए और भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए। यह दिशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार तभी कमजोर होगा जब शिकायत करने वाला नागरिक स्वयं को असहाय नहीं, व्यवस्था का सक्रिय भागीदार महसूस करेगा। हम 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज सड़कों, बड़े उद्योगों और विशाल अर्थव्यवस्था का नाम नहीं है। विकसित भारत वह होगा जहां नागरिक को अपना वैध काम कराने के लिए किसी की जेब गर्म न करनी पड़े, जहां पद प्रतिष्ठा का नहीं, उत्तरदायित्व का प्रतीक हो, जहां कानून प्रभावशाली और सामान्य नागरिक के लिए अलग-अलग न हो।

शाहजहांपुर का कथित वीडियो जांच का विषय है, लेकिन उससे उठने वाला सवाल पूरे देश का है। गंगाजल हाथ में लेकर भ्रष्टाचार के बंटवारे की कथित शपथ यदि सच साबित होती है तो यह केवल कुछ व्यक्तियों का नैतिक पतन नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन के लिए एक कठोर चेतावनी होगी। और यदि वीडियो भ्रामक या संपादित पाया जाता है, तब भी ऐसी सामग्री का तेजी से फैलना बताता है कि भ्रष्टाचार को लेकर समाज में अविश्वास कितना गहरा है। संबंधित पार्षदों ने वीडियो को लेकर संपादन और बदनाम करने का आरोप भी लगाया है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब समय है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल भाषण न दें, व्यवस्था को ऐसा बनाएं जिसमें भ्रष्टाचार करना कठिन, छिपाना असंभव और ईमानदारी से काम करना सहज हो। क्योंकि राष्ट्र की असली आजादी उस दिन होगी, जब किसी नागरिक को अपना अधिकार पाने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। भ्रष्टाचार की शपथ नहीं-ईमानदारी का संस्कार चाहिए। सिर्फ ह्यन खाऊंगा, न खाने दूंग नहीं-ह्यन सहूंगा, न सहने दूंगा का नागरिक संकल्प चाहिए। यही संकल्प विकसित भारत की नैतिक नींव बन सकता है।

लेखक – ललित गर्ग
(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

दिल्ली में 16 साल की किशोरी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली में 16 साल की एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया, जिनमें तीन नाबालिग हैं। आरोपियों ने बाद में लड़की के शव को खुले इलाके में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि शव की हालत इतनी खराब थी कि उसके कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों ने खा लिया था। यह मामला 13 सितंबर को सामने आया जब उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास एक बुरी तरह सड़ी-गली लाश मिली। शव की हालत ऐसी थी कि पुलिस शुरू में यह भी तय नहीं कर पाई कि शव लड़के का है या लड़की का।

60 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन की टीम ने गुजरात के खेड़ा निवासी 24 वर्षीय आरोपी यश कैलाश बुलचंदानी को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का एक मामला सुलझाया है। ऑपरेशन के दौरान, उसके पास से लगभग 96 ग्राम पिघला हुआ सोना, सोने के दो सिक्के, सोने की एक चेन, हीरे का एक सेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी ने एक महीने पहले वारदात को अंजाम दिया था।

भजनपुरा में धंसती सड़कों से जल्द मिलेगी राहत, पुरानी सीवर लाइन बदलेगा जल बोर्ड

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। भजनपुरा और आसपास के इलाकों में धंसती सड़कों और उफनती सीवर लाइनों की समस्या झेल रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र के साउथ गामड़ी इलाके में जर्जर सीवर लाइन बदलने की कवायद शुरू कर दी है। साढ़े चार पुश्ता और ए-ब्लॉक में पुरानी सीवर लाइन को हटाकर नई लाइन बिछाई जाएगी। परियोजना को 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस काम में पहली बार पारंपरिक कंक्रीट पाइपों के स्थान पर एसएन-8 स्ट्रक्चर्ड वॉल पॉलिथीन के डबल-वॉल पाइप इस्तेमाल किए जाएंगे। जल बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के मुताबिक, पुराने कंक्रीट पाइप लंबे समय तक सीवर के रासायनिक प्रभाव, नमी और जमीन के दबाव को सहन नहीं कर पाते। पाइप कमजोर होने के बाद उनके टूटने से आसपास की मिट्टी खिसकती है और सड़क धंसने की स्थिति बनती है। नए पाइप रासायनिक क्षरण और जंग से प्रभावित नहीं होते। ये जमीन के दबाव को बेहतर ढंग से सहन कर सकते हैं। इससे सीवर नेटवर्क की टिकाऊ क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

सड़कों की बेहतर निगरानी के लिए हर सप्ताह निरीक्षण अनिवार्य

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। सड़कों की बेहतर निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारियां तय की हैं। विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अधीक्षण अभियंता प्रत्येक शनिवार अपने रोड मेंटेनेंस सर्कल में किसी एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) के अधीन सड़क का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद शाम तक एक निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डिप्टी सेक्रेटरी (इंस्पेक्शन) को सौंपेंगे, जिसकी प्रति चीफ इंजीनियर और इंजीनियर-इन-चीफ को भी भेजी जाएगी। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इससे निगरानी बेहतर होने पर सड़कों के रखरखाव में लापरवाही या देरी नहीं होगी। इसमें यह भी तय किया गया है कि कनिष्ठ अभियंता और उद्यान विभाग के एसओ को हर हफ्ते कम से कम 6 घंटे सड़कों का निरीक्षण करना होगा।

चौथे दिन भी डीटीसी बसें ठप, मेट्रो में उमड़ी भारी भीड़

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

दिल्ली में डीटीसी चालकों की हड़ताल चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी है। जिसका सीधा असर मेट्रो रेल में देखने का मिल रहा है। ऐसे में कामकाजी लोग, पर्यटक और खरीदार मेट्रो यात्रा का रुख कर रहे हैं। इसके चलते आम दिनों के मुकाबले मेट्रो ट्रेन खचाखच भरी है। यह नजारा केंद्रीय सचिवालय से दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो वाली लाइन का है। डीयू में आज छात्र संघ का भी चुनाव है तो उसका सभी असर देखने को मिल रहा है।

यात्रियों का कहना है कि अब मेट्रो ट्रेन की सुविधा हर क्षेत्र तक पहुंच गई है। इसलिए उन्हें बस हड़ताल से उतनी अधिक परेशानी नहीं हो रही है। जैसा पहले के मामलों में होता था। लोग ई-रिक्शा से नजदीकी मेट्रो स्टेशन पहुंचकर उससे सफर तय कर रहे हैं। इस पूरे मामले में ई-रिक्शा चालकों के भी कमाई कई गुना तक बढ़ गई है।

एसओएल-एनसीवेब छात्रों के मुद्दों को डूसू चुनाव में जगह देने की मांग

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) और नॉन-कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) के छात्रों की समस्याओं को लेकर स्वाभिमान मार्च निकाला। संगठन ने आरोप लगाया कि डूसू चुनाव लड़ रहे किसी भी छात्र संगठन के घोषणापत्र में एसओएल और एनसीवेब के करीब छह लाख छात्रों की समस्याओं को जगह नहीं दी गई है। केवाईएस के मुताबिक, इन छात्रों के पास डूसू चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। एसओएल और एनसीवेब में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र सरकारी स्कूलों और वंचित वर्गों से आते हैं।

डूसू चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026-27 के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में छात्रों ने मतदान प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने दावा किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने सामाजिक न्याय, समानता और विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक भविष्य के पक्ष में मतदान किया है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने मतदान संपन्न होने के बाद कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस और पूरी व्यवस्था के भारी दबाव के बावजूद एनएसयूआई के कार्यकर्ता पूरे चुनाव के दौरान मजबूती से डटे रहे। उन्होंने कहा कि छात्रों ने सामाजिक न्याय और समानता के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन दिखाया है। संगठन को पूरा विश्वास है कि एनएसयूआई चारों सीटों पर निर्णायक जीत हासिल कर 4-0 से ऐतिहासिक परिणाम देगी। एनएसयूआई ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नफरत, विभाजन और भय की राजनीति को पूरी तरह खारिज करने तथा सभी के लिए एक समावेशी परिसर का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। संगठन ने दोहराया कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरह से यहां के छात्रों का है और उनका जनादेश न्याय, समानता और बेहतर भविष्य के लिए होगा।

क्रिकेट टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास से 19 आरोपी पकड़े गए

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। क्रिकेट मैच की टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्रिकेट मैच के टिकटों को ज्यादा कीमत पर गैर-कानूनी तरीके से बेचने और कालाबाजारी करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

दरअसल, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम अफगानिस्तान फ्रेंडशिप कप टी-20 क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम और उसके आस-पास के इलाकों में क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी, दलाली और गैर-कानूनी तरीके से दोबारा बिक्री के बारे में खास जानकारी मिली थी। इसके बाद आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश कुमार की देखरेख में एक खास एंटी-टाउटिंग टीम बनाई गई। टीम ने स्टेडियम के आसपास खुफिया जानकारी जुटाने, चुपचाप जांच-पड़ताल करने और निगरानी रखने का काम किया। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन और उससे सटे इलाकों जैसी संवेदनशील जगहों पर भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बीट स्टाफ तैनात किए गए।

तैनात टीमों को खास तौर पर निर्देश दिए गए कि वे संदिग्ध लोगों की पहचान करें, टिकट की दलाली के बारे में स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाएं और मैच के टिकटों की गैर-कानूनी बिक्री या दोबारा बिक्री में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध लोगों पर चुपके से नजर रखी गई और उनकी गतिविधियों की पुष्टि की गई। मैच टिकटों की गैर-कानूनी बिक्री, री-सेल की पुष्टि करने के लिए जहां भी जरूरत थी, वहां डिकॉय कस्टमर (नकली ग्राहक) तैनात किए गए। शामिल लोगों की पहचान और पुष्टि के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ा गया।

जांच के दौरान पता चला कि कुछ आरोपियों ने टिकट कम कीमत पर खरीदे थे और वे उन्हें दर्शकों को काफी ज्यादा कीमत पर दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे थे। बरामद टिकटों के सोर्स और आरोपियों तक उनके पहुंचने की प्रक्रिया की पुष्टि की जा रही है।

क्रिकेट मैच के टिकट बरामद किये गये

13, 15 और 17 सितंबर को चलाए गए स्पेशल अभियान के दौरान आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन में कुल 13 मामले दर्ज किए गए। कुल 19 आरोपियों को पकड़ा गया और 71 क्रिकेट मैच टिकटों के साथ 7,400/- नकद बरामद किए गए। 14 सितंबर को चार मामले में पांच आरोपियों को पकड़ा गया और 29 क्रिकेट मैच टिकटों के साथ 3,400 रुपये बरामद किए गए। 15 सितंबर को दस आरोपियों को पकड़ा गया और 31 क्रिकेट मैच टिकटों के साथ 4,000 रुपये नकद बरामद किए गए। 17 सितंबर को तीन मामले दर्ज किए गए और चार आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से कुल 11 क्रिकेट मैच के टिकट बरामद किए गए।

हाथ में सामान वाले यात्रियों के लिए अलग प्रवेश

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। आईजीआई एयरपोर्ट पर हाथ में सामान लेकर या बिना सामान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलग प्रवेश की सुविधा शुरू की गई है। डायल ने एक्सप्रेस@डेल सेवा शुरू की है, जिसके तहत ऐसे यात्रियों को सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से अलग मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। इससे टर्मिनल में प्रवेश की प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। डायल के अनुसार, यह सुविधा टर्मिनल-1 के गेट संख्या 5 से शुरू की गई है। इसके अलावा टर्मिनल-2 में गेट संख्या 1 और टर्मिनल-3 में गेट संख्या 2 को इसके लिए निर्धारित किया गया है। यह सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए है, जिन्हें चेक-इन सामान जमा नहीं करना है।

दिल्ली से गुजरात तक फैले नार्को-एक्सटॉर्शन नेटवर्क पर कार्रवाई

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)

दिल्ली से गुजरात तक फैले नार्को-एक्सटॉर्शन नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा शिकंजा कसा है।

दिल्ली पुलिस और गुजरात क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में 2 किलो पाकिस्तानी मूल की हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 31 साल के कुलदीप स्वामी के रूप में हुई है, जो राजस्थान के चुरू का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, कुलदीप स्वामी एक बड़े नार्को-एक्सटॉर्शन मॉड्यूल का हिस्सा था और गुजरात के वडोदरा में दर्ज करीब 10 करोड़ रुपए के हाई-प्रोफाइल एक्सटॉर्शन केस में वॉन्टेड था।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 किलो हाई-क्वालिटी हेरोइन, एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार और हवाला टोकन वेरिफिकेशन में इस्तेमाल होने वाला करेंसी नोट बरामद किया है। खास बात यह है कि बरामद कार में एक सीक्रेट कैविटी भी बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल नशे की तस्करी के लिए किया जाता था।

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। जांच में इस नेटवर्क के तार गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना से जुड़े होने के साथ-साथ पाकिस्तान से जुड़े नारकोटिक्स लिंक की भी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि यह गैंग नशे की तस्करी से मिले पैसों से एक्सटॉर्शन और अन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है।

गाजीपुर 220 केवी सबस्टेशन का होगा कायाकल्प

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी जिले में बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और मानसून के दौरान पावर ट्रिपिंग के खतरों को खत्म करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने योजना तैयार की है। ईस्ट दिल्ली के पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले 220 केवी गाजीपुर सबस्टेशन के यार्ड का कायाकल्प और रीमॉडलिंग की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सबस्टेशन परिसर के यार्ड का पुनर्विकास, खस्ताहाल हो चुकी केबल ट्रेंचों (नालियों) का नवनिर्माण और ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा।

दिल्ली की अदालत ने आतंकी साजिश मामले में अमेरिकी नागरिक वैन डाइक को जमानत दी

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से जांच किए जा रहे आतंकी साजिश के एक मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक को शुक्रवार को जमानत दे दी।

अदालत के सूत्रों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने वैन डाइक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।

अदालत ने निर्देश दिया कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। अदालत ने वैन डाइक की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को एनआईए को नोटिस जारी किया था। इस महीने की शुरूआत में एजेंसी ने वैन डाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों के खिलाफ भारत में कथित अवैध प्रवेश, ठहरने और आवाजाही को लेकर आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान नहीं लगाए थे। एनआईए के आरोपपत्र में सातों आरोपियों पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धारा 21 (वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने की सजा का प्रावधान) और धारा 23 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है, यूएपीए के तहत अपराध किए जाने के संबंध में सही और पूरी जानकारी जुटाने तथा उसका सत्यापन करने के लिए और समय की आवश्यकता है।

साजिश के मामले में की जा रही है जांच

एनआईए ने अदालत को बताया था कि आरोपियों के खिलाफ भारत और म्यांमा में जातीय सशस्त्र समूहों को सहायता देने और उन्हें ड्रोन प्रशिक्षण देने सहित व्यापक आतंकवादी साजिश के मामले में जांच की जा रही है।

डुसू चुनाव में हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, विजय जुलूस पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डुसू) चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव के दौरान जीत के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ रहे सभी छात्र संगठनों और 140 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर सामूहिक चुनावी हजार्ना क्यों न लगाया जाए।

कोर्ट ने बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के काफिले और हथियारों के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सभी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तस्वीर को देखकर जिसमें एक छात्र को बंदूक लहराते हुए दिखाया गया है, कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये छात्र कैसे हो सकते हैं। खुलेआम हथियार दिखा रहे हैं। ये वास्तविक छात्रों के मौकों को खा रहे हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में डीयूएसयू चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ह्ललोकतंत्र को आपराधिक समाज में नहीं बदला जा सकता। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद यह सब कैसे हुआ?

कोर्ट ने डीसीपी नॉर्थ से सवाल किया कि दिल्ली की सड़कों पर और नॉर्थ कैंपस के अंदर और आसपास बिना नंबर प्लेट और कैंडिडेट्स के नाम वाली एक भी गाड़ी को जाने की कैसे इजाजत दी गई? आप फोटो से इनकार नहीं कर सकते। 10-20 कारों का एक बड़ा काफिला था। इसकी इजाजत कैसे दी गई? अगर आप कहते हैं कि आपने काफी फोर्स तैनात की थी, तो इसकी इजाजत कैसे दी गई? इस पर डीसीपी नॉर्थ ने कहा कि हम लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इन गाड़ियों के काफिले से डर, आतंक और दबदबे की भावना पैदा होती है। आपने रोकने के लिए क्या कदम उठाए? उम्मीदवार कार की छत और आगे के बोनट पर खड़े हैं। क्या यह गुंडागर्दी नहीं है?

सुनवाई के दौरान एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 998 चालान किए गए हैं। जो वीडियो में दिख रहे हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरसी भी जब्त की जाएंगी। 6 एफआईआर और 4 अरेस्ट हुए हैं। जहां तक ट्रैफिक की बात है, तो इन सभी बिना लाइसेंस वाले वाहनों के 5,737 चालान किए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि टीचर पर हमले का क्या हुआ? क्या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति स्टूडेंट है? इस पर एएसजी ने गिरफ्तार किए जाने की बात कही।

दिल्ली पुलिस ने नार्को-एक्सटॉर्शन नेटवर्क का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान में बनी 2 किलो हेरोइन जब्त

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में दिल्ली और गुजरात के बीच चल रहे नार्को-एक्सटॉर्शन नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और पाकिस्तान में बनी 2 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है।

पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान राजस्थान के चुरू के रहने वाले 31 साल के कुलदीप स्वामी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक, स्वामी एक बड़े नार्को-एक्सटॉर्शन नेटवर्क में शामिल था और गुजरात के वडोदरा में दर्ज लगभग 10 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के एक हाई-प्रोफाइल मामले में वांछित था।

जांच के दौरान, पुलिस ने 2 किलो अच्छी क्वालिटी की हेरोइन, एक कार और हवाला टोकन वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नोट बरामद किए। पुलिस ने बताया कि बरामद गाड़ी में एक गुप्त खाना (कैविटी) भी मिला। जांचकर्ता अब इस नेटवर्क के गैंगस्टर गोदारा और डेलाना के साथ कथित संबंधों और पाकिस्तान स्थित नशीले पदार्थों के नेटवर्क से संभावित कनेक्शन की जांच कर रहे हैं।

यह ताजा कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन वसूली, नशीले पदार्थों और हथियारों से जुड़े अपराधों में शामिल आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे कई ऑपरेशनों के बीच हुई है। इससे पहले, 26 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी गैंग के दो कथित समर्थकों को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर जबरन वसूली से जुड़े अपराध करने की योजना बना रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों की पहचान नरेला के रहने वाले 22 साल के चिराग और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 26 साल के सागर के तौर पर की थी। अधिकारियों ने बताया कि एक सूचना के आधार पर 19 अगस्त को मुनक नहर के पास दोनों को गिरफ्तार किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, उनके पास से .32 बोर की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और चार कारतूस, देसी सिंगल-शॉट पिस्तौल और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। एक अन्य मामले में, 19 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने एक घोषित अपराधी को पकड़ा, जो दिल्ली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी से बच रहा था।

भगोड़ा घोषित कर दिया था

आरोपी की पहचान हरियाणा के अंबाला के रहने वाले 26 साल के जसविंदर सिंह के तौर पर हुई। वह जगतपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत दर्ज एफआईआर में वांछित था। पुलिस ने कहा था कि केस दर्ज होने के बाद से ही सिंह फरार था और बाद में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

यूपीआई पर शुल्क लगाकर सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला: उदित राज

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वेब वार्ता)। कांग्रेस नेता उदित राज ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले लोगों को यूपीआई के जरिए भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया और अब इसी पर शुल्क लगाकर जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यूपीआई से पेमेंट करने के लिए सरकार ने लोगों को उत्साहित किया। इसके बाद उनकी जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया गया। 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू होगा। 2000 से ऊपर वाले ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इस पर शुल्क लगाना सीधे तौर पर यह जनता की जेब की लूट है। उदित राज ने कहा कि सरकार पहले से ही पेट्रोल और डीजल पर भारी एक्साइज ड्यूटी तथा जीएसटी के माध्यम से जनता से पैसा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। उदित राज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ह्ययुवा धर्म संसदह्व कार्यक्रम को लेकर कहा कि जेन-जी अपने आप नहीं आती; उसका एक सिस्टम है। संघ के कई अनुषांगिक संगठन हैं और भाजपा भी है। यही लोग जेन-जी को ऑगेनाईज करके लाते हैं। जो जेन-जी उनके समर्थक हैं, उन्हीं को वहां लाया जाता है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि ओपन हाउस में जेन-जी को बुलाएं।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया से गायब दो नाबालिग को जीआरपी ने सकुशल किया बरामद

वेब वार्ता, कानपुर। पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी० द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व मे आपरेशन मुस्कान के अंतर्गत सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि जनपद देवरिया से दो नाबालिग गायब हुए है। सूचना मिलते ही बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी गई। खोजबीन के दौरान ट्रेन नेता जी एक्सप्रेस में दोनों बालक मिल गए। पूछने पर दोनों ने अपना नाम रामजी यादव (16) पुत्र सुवंश यादव नि. मो0 रघवापुर वार्ड जिला देवरिया व भांजा 14 वर्षीय श्याम प्रताप यादव (काल्पनिक) पुत्र शिवाकान्त यादव बताया।

बालकों ने बताया कि वह घर से भाग आए थे। जीआरपी पुलिस ने थाना कोतवाली सदर जनपद देवरिया पुलिस को सूचित करते हुए पुलिस टीम सहित परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस सराहनीय कार्य के लिये गुमशुदा बालकों के परिजनों द्वारा थाना जीआरपी पुलिस कानपुर सेन्ट्रल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया।

आयुष्मान कार्ड निर्माण शिविर आयोजित

देवरिया, 18 सितम्बर,। देवरिया जिले में जिलाधिकारी के निदेर्शानुसार शून्य गरीबी में चिन्हित पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर तहसील सभागार, देवरिया में विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण शिविर आयोजित किया गया।

कुशीनगर के अल्फाज शेख नेपाल को दी गई दान पहुचीं नेपाल

कुशीनगर 18 सितम्बर। नेपाल में आई त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुशीनगर के अल्फाज शेख (6) ने अपनी गुल्लक की पूरी बचत दान कर दी। दो देशों का मामला होने के कारण मदद की राशि नेपाल सरकार तक पहुंचाना आसान नहीं था। केंद्रीय मंत्रालय की मदद से 14 दिन की प्रक्रिया पूरी कर नेपाल सरकार के दूतावास को बृहस्पतिवार को गुल्लक सौंप दिया गया। नेपाल सरकार ने मासूम की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी आईडी से सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

कुशीनगर के अल्फाज शेख नेपाल को दी गई दान पहुचीं नेपाल

कुशीनगर 18 सितम्बर। नेपाल में आई त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुशीनगर के अल्फाज शेख (6) ने अपनी गुल्लक की पूरी बचत दान कर दी। दो देशों का मामला होने के कारण मदद की राशि नेपाल सरकार तक पहुंचाना आसान नहीं था। केंद्रीय मंत्रालय की मदद से 14 दिन की प्रक्रिया पूरी कर नेपाल सरकार के दूतावास को बृहस्पतिवार को गुल्लक सौंप दिया गया। नेपाल सरकार ने मासूम की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी आईडी से सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

सपा कार्यकर्ताओं ने बूट पोलिश कर मनाया बेरोजगार दिवस

देवरिया 18 सितम्बर। देवरिया जिले में सपा के यूथ फ्रंटल के कार्यकताओं ने गुरुवार के दिन लगभग एक बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर बूट पालिश कर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कार्यकताओं ने सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार नहीं दिये जाने का आरोप लगाया। इसका नेतृत्व कर रहे लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष दिव्यांग श्रीवास्तव ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार देने में असफल है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा और जनकल्याण की भावना के साथ रक्तदान करे : सूर्य प्रताप शाही

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। रक्त की आवश्यकता किसी भी मरीज को कभी भी पड़ सकती है और ऐसे समय में रक्तदाता का योगदान किसी जरूरतमंद के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा और जनकल्याण की भावना के साथ आयोजित रक्तदान शिविर लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है।

ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सेवा की भावना को जनभागीदारी से जोड़ना है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े सेवा कार्यों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना मजबूत होती है। उन्होंने रक्तदान करने वाले सभी लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं।

सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन बचाने में सहायक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान जैसे सेवा कार्यों का आयोजन समाज में सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है।

रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए पात्र लोगों से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की।

इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एचके मिश्र, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक पंडित गिरीश चंद्र तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश मणि, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र सिंह, भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।

स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़कर ही नगर को बेहतर बनाया जा सकता : विनय जायसवाल

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर में विश्वकर्मा जयंती एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में नगर में ह्यसेवा संकल्प अभियानह्व के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना एवं माल्यार्पण, स्वच्छता अभियान, दीप प्रज्ज्वलन, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं दीपदान तथा दीपोत्सव सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ सुभाष चौक पर नगरपालिका परिषद द्वारा स्थापित भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा पर अध्यक्ष श्री जायसवाल द्वारा विधिवत पूजन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान की शुरूआत की गई। उपस्थित लोगों ने भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए समाज और राष्ट्र की उन्नति, श्रम एवं कौशल के सम्मान तथा जनसेवा के संकल्प को दोहराया। इसके बाद जूनियर हाईस्कूल परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरूआत की गई। पालिकाध्यक्ष ने स्वयं सफाई अभियान में सहभागिता करते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर नगर केवल नगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़कर ही नगर को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके पश्चात नगरपालिका कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं।

इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीघार्यु एवं राष्ट्रसेवा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। सेवा संकल्प अभियान के क्रम में शाम 07 बजे श्री बुढ़िया माता मंदिर परिसर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित कर नगर एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की गई। इसके साथ ही तिलक चौक से गांधी चौक तक विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों की साफ-सफाई कराई गई। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जी श्रम, सृजन, कौशल और निर्माण के प्रतीक हैं।

सशक्त नगर का निर्माण करना इसी भावना का हिस्सा है

प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के साथ ही दीपदान किया गया। इस दौरान नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए महापुरुषों के आदर्शों को स्मरण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा और विकास का लाभ पहुंचाना तथा स्वच्छ, स्वस्थ एवं सशक्त नगर का निर्माण करना इसी भावना का हिस्सा है।

आयुष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिक्षण शिविर का आयोजन

मुरादाबाद, वेब वार्ता

कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को आयुष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। माह की प्रत्येक 18 तारीख को आयोजित होने वाले इस शिविर का उद्देश्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने वाले फरियादियों के साथ-साथ आमजन को सहज रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

शिविर की खास बात यह रही कि यहां आने वाले लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेने का अवसर मिला। शुक्रवार को आयोजित कैंप में लगभग 300 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण और आयुष चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। लोगों की बढ़ती भागीदारी से साफ नजर आया कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के प्रति आमजन की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया भी शिविर में पहुंचे और वहां स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए चिकित्सकों से भी सेवाओं के संबंध में चर्चा की। डीएम की मौजूदगी से शिविर में पहुंचे फरियादियों का उत्साह भी बढ़ा। आयुष चिकित्सा शिविर की यह पहल जिला प्रशासन की जनकल्याणकारी सोच और स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन के करीब पहुंचाने की दिशा में सराहनीय कदम मानी जा रही है। खासतौर पर जिला मुख्यालय आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के फरियादियों के लिए एक ही परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सकीय परामर्श मिलना उपयोगी साबित हो रहा है।

इनकी रही मौजूदगी

शिविर में डॉ. अमरदीप नायक, डॉ. विधूशेखर मलिक, जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, डॉ. पवन नायक, होम्योपैथी केंद्र प्रभारी, योग प्रशिक्षक गौरव त्यागी, डॉ. अंजली समेत अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा नियमित जांच और संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। माह की 18 तारीख को होने वाला यह आयोजन आयुष चिकित्सा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है।

भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प एवं तकनीकी कौशल का प्रतीक माना जाता; पुलिस अधीक्षक

वेब वार्ता, देवरिया। देवरिया जिले में शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के अवतरण दिवस के अवसर पर आज दिनांक 17.09.2026 को अभिजित आर. शंकर, पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन स्थित परिवहन शाखा में परम्परागत रूप से आयोजित विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा में रखे वाहनों एवं शस्त्रों सहित उपकरणों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई तथा देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा से पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण एवं उनके परिवारों की सुख-समृद्धि, सुरक्षा एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई।

सुरक्षा सुनिश्चित होती है

पूजन कार्यक्रम के उपरान्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को मिष्ठान वितरित कर विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएँ दी गईं। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प एवं तकनीकी कौशल का प्रतीक माना जाता है। पुलिस विभाग के कार्यों में प्रयुक्त वाहन, शस्त्र एवं विभिन्न उपकरण महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिनकी नियमित देखभाल एवं उचित रख-रखाव से पुलिस की कार्यक्षमता एवं सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, एएसपी/क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी परिवहन शाखा सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

परशुरामपुरी के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान न होने पर मुख्यमंत्री से गुहार

परशुरामपुरी। नगर पालिका परिषद परशुरामपुरी के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार बागीश मणि त्रिपाठी को सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 29 जुलाई, 3 सितंबर और 5 सितंबर को प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों के अनुसार, 4 सितंबर को नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष और सभासदों के साथ हुई वार्ता में समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारियों से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया था।

मुशायरा ग्राउंड में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन

मुरादाबाद, वेब वार्ता

जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए की गई तैयारी एवं जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया था कि अपराह्न 12:00 बजे जैसे ही आपातकालीन सायरन की आवाज सुनाई दे तत्काल दौड़ते हुए सभी अधिकारी व कर्मचारी कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में इकट्ठा हो इन्ही निदेर्शों का पालन करते हुए शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे जैसे ही सायरन बजे तमाम कर्मचारी व अधिकारी मुशायरा ग्राउंड पहुंचे जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैंसिया अपर जिलाधिकारी प्रशासन एडीएम फाइनेंस ममता मालवीय सहित अनेक अधिकारी एवं भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी मुशायरा ग्राउंड में इकट्ठा हुए जहां अधिकारियों द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया देखा गया कि कर्मचारी कितने जागरूक हैं मॉक ड्रिल की बात करें तो यह किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने वाला एक पूर्वाभ्यास है जिसे आसान शब्दों में कहीं तो यह वास्तविक संकट अर्थात भूकंप आगजनी की बड़ी घटना घटित होने से पहले उसकी तैयारी जांचने का एक तरीका है यही सब कलेक्ट्रेट में मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिला

एडीएम फाइनेंस ममता मालवीय ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश के 34 जनपदों एवं 156 तहसीलों में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया उन्होंने बताया कि भूकंप आगजनी की बड़ी घटनाएं आदि आपदा स्थिति में स्वयं को कैसे सुरक्षित करें यह सब मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया सायरन आपदा का संकेत है।

उन्होंने बताया कि मुरादाबाद जनपद में जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए एक होटल विद्यालय प्रतिष्ठान और एक अस्पताल को चिन्हित किया गया था और इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करते रहें सायरन की आवाज सुनकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया भी कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड पहुंच गए थे जहां पहले से ही तमाम कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

बहराइच पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

वेब वार्ताद्व बहराइच ।साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन CyVajra अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक, बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु दिए गए निदेर्शों के क्रम में थाना खैरीघाट पुलिस एवं स्वाट टीम को साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार

थाना हरदी पुलिस को वादी प्रमुख पुत्र दूजी नि0 ग्राम सिसैय्या चूड़ामणि थाना हरदी बहराइच तथा नारायण वर्मा पुत्र परमेश्वर निवासी सिकन्दरपुर थाना हरदी बहराइच द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि विपक्षीगण ने लोन कराने के नाम पर

कूटरचित ढंग से उसका विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाया तथा उक्त खाते में उनके मोबाइल नंबर लिंक करा दिये। तत्पश्चात अभियुक्तों ने वादी की पासबुक, एटीएम, चेकबुक, मोबाइल नम्बर अपने कब्जे में रखकर विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी की। वादी को इसकी जानकारी होने तथा इसका विरोध करने पर विपक्षीगण ने उनके साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी तथा डरा-धमकाकर क्रमशः दोनों वादियों से 2,40,000 व 4800 भी उनके बैंक खातों से निकलवा लिए। उक्त तहरीर के आधार पर थाना हरदी में क्रमशः मु0अ0सं0 319/26 व 320/26 धारा 318(4), 308(5), 352, 351(3) बीएनएस व 66ऊ आईटी एक्ट बनाम सुफियान पुत्र मो0अय्यूब,समीर अहमद पुत्र जलील अहमद व कृष्णा मुरारी प्रसाद पुत्र भगत प्रसाद पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

रिजर्व पुलिस लाइन, कुशीनगर में विधि-विधान के साथ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन

कुशीनगर 17 सितम्बर। कुशीनगर जिले के आज दिनांक 17 सितम्बर, 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन, स्थित परिवहन शाखा में भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर्षोल्लास एवं पूर्ण विधि-विधान के साथ सम्पन्न हुई।

पूजा के दौरान पुलिस अधीक्षक एवं उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूर्ण धार्मिक विधि-विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन-अर्चन किया गया। पूजन के उपरांत परिवहन शाखा के वाहनों एवं शासकीय उपकरणों की सुरक्षा, उनके सुचारू संचालन तथा जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कामना की गई। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित समस्त अधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं आगंतुकों को प्रसाद वितरित किया गया। इस शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर केशव कुमार द्वारा परिवहन शाखा में पूजा-अर्चना की गई। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर सिद्धार्थ वर्मा,क्षेत्राधिकारी (लाइन) जयंत यादव प्रतिसार निरीक्षक, कुशीनगर तथा परिवहन शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मी उपस्थित रहे।

मंत्रीमंडल ने ईपीएफओ वेतन सीमा 15 से बढ़ाकर कि 25 हजार रुपये

अनिवार्य कवरेज का होगा विस्तार, कर्मचारियों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा बल

वेब वार्ता, कानपुर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह वृद्धि 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी होगी। इसकी घोषणा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस निर्णय से बड़ी संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण तक पहुंच का विस्तार होगा।

ईपीएफओ कानपुर के क्षेत्रीय आयुक्त (प्रथम) शाहिद इकबाल ने ईपीएफओ कार्यालय के सभागार में पत्रकारवार्ता कर बताया कि केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए संवैधानिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है,जिससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। संशोधित वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 को

विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी होगी। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लागू ईपीएफओ योजनाओं के तहत भविष्य निधि बचत, पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वेतन, न्यूनतम मजदूरी और जीवन-यापन की लागत में इस वृद्धि के बावजूद, वेतन सीमा सितंबर 2014 से अपरिवर्तित थी। वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर किसी प्रतिष्ठान में शामिल होने वाले कर्मचारी, लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन, अनिवार्य ईपीएफ व्यवस्था के तहत स्वतः कवर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतन सीमा के साथ, 15,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी अनिवार्य कवरेज के लिए पात्र हो जाएंगे, जिससे औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का दायरा और विस्तृत हो जाएगा।

इस निर्णय से कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलने के साथ-साथ श्रमिकों के कार्यबल को स्थिरताव मजबूत करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय आयुक्त श्री इकबाल ने बताया कि इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और 16 जून 2026 को आयोजित बैठक में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इसकी सिफारिश की। वेतन सीमा में वृद्धि के कारण सरकार पर होने वाला वार्षिक अतिरिक्त व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में वार्षिक बजटीय सहायता लगभग 10,250 करोड़ रुपये है। 5-वर्ष की अवधि में अनुमानित व्यय लगभग 56,696 करोड़ रुपये होगा।

गुरुग्राम के बाद दिल्ली में हिट एंड रन!

बाइक को 500 मीटर तक घसीटता रहा कार सवार, एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है. गुडगांव के बाद अब दिल्ली में हिट एंड रन का केस सामने आया है. आरके पुरम इलाके में एक कार ने बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद 500 मीटर तक घसीटा. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि बीती रात दिल्ली के आरके पुरम इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक मोटरसाइकिल कार के नीचे फंसी हुई और कार के साथ कुछ मीटर तक घिसटती हुई दिख रही है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में ऋक्षक्षदर्ज कर ली गई है. कार ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और गाड़ी जब्त कर ली गई है. वायरल वीडियो में लोगों ने कार का पीछा करके कार रोकी और आरोपी के साथ हाथापाई भी की. वीडियो में दिख रहा आरोपी अधेड़ दिख रहा है.

पुलिस ने अनुसार, 17 सितंबर को रात करीब 10:00 बजे मुनिरका गांव का रहने वाला तनिष टोकस अफ्रीका एवेन्यू रोड पर सड़क किनारे अपनी बाइक पर बैठा था. इसी दौरान 73 साल के वेणु गोपाल कार से भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहा था. तभी यह हादसा हुआ. हादसे के बाद तनिष बाइक से गिर गया और कार से बाइक घसीटती चली गई. लोगों के मुताबिक, करीब 500 मीटर तक बाइक कार के बोनट के नीचे घसीटती रही. इस दौरान बाइक से भयंकर चिंगारी निकलती रही. हादसे में तनिष को मामूली चोटें आई हैं. मामले में आरके पुरम पुलिस स्टेशन में इठर की धारा 281/125( ) के तहत ऋक्षक्षदर्ज की गई है. जांच के दौरान, दुर्घटना करने वाली नीले रंग की कार को जब्त कर लिया गया है और आरोपी ड्राइवर वेणु गोपाल को पकड़ लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने साफ किया आरोपी की भी मेडिकल जांच की गई और उसमें शराब का कोई अंश नहीं पाया गया.

गुडगांव हिट एंड रन में क्या हुआ था?

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर 13 सितंबर को महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया के साथ हुए हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी. सिया बाइकर्स के एक समूह के साथ जा रही थीं, तभी एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. सिया ने आरोप लगाया था कि कार सवारों ने पहले उनका पीछा किया और फिर जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मारी.

घटना का वीडियो बाइक और हेलमेट पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुआ था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में जांच तेज की और मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला तथा उसके साथ मौजूद लवनीश को राजस्थान से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बाद में मामले में हत्या के प्रयास, पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराएं भी जोड़ीं.

हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचे गायक

चंडीगढ़। मशहूर हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया एक बड़ी साजिश का शिकार होने से बाल-बाल बच गए हैं. उनकी रेंज रोवर कार पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. इस भयानक और जानलेवा हमले के दौरान गनीमत यह रही कि सिंगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वे सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे.

सोशल मीडिया पर ली गई हमले की जिम्मेदारी

गोलीबारी की इस वारदात के कुछ ही देर बाद अनिल पंडित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली. इस पोस्ट के जरिए गायक को सीधे तौर पर धमकाते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने आगे से फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो अगली बार गोली सीधे उनकी छाती में उतारी जाएगी. हमलावरों ने बिना किसी खौफ के इस पूरी वारदात को अंजाम देने का खुला दावा किया है. वायरल हो रही पोस्ट में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई इस फायरिंग के पीछे हिमांशु सोनीपत, हरि बॉक्सर, हरमन संधू और अनिल पंडित का हाथ है.

जानें कौन है दिलेर सिंह खरकिया

हरियाणवी संगीत जगत के चर्चित नाम दिलेर सिंह खरकिया का जन्म 8 अगस्त 1997 को हरियाणा के खरक गांव में हुआ था गायकी का हुनर उन्हें अपने पिता राजेंद्र खरकिया से विरासत में मिला, जो खुद एक प्रसिद्ध रागनी गायक हैं. अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए दिलेर ने भी संगीत को ही अपना जुनून और करियर चुना. अपनी बेहतरीन आवाज के दम पर आज वह हरियाणा के सबसे लोकप्रिय गायकों में शुमार हैं. 'मोटो', 'विश', 'कबूतरी' 'लिलो चमन' और 'हाई कोर्ट' जैसे सुपरहिट गानों ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम और प्रशंसकों के बीच खास पहचान दिलाई है.

कार में 7 घंटे तक लाश लेकर घूमता रहा कपल, नाले में फेंका; पूर्व सहकर्मी और पति गिरफ्तार

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट से 6 सितंबर को लापता हुए सरिता विहार निवासी 31 वर्षीय युवराज सिंह मनचंदा की हत्या के मामले में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं।

पुलिस ने युवराज की पूर्व ऑफिस सहकर्मी अन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। दोनों को बृहस्पतिवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस के मुताबिक, फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सक युवराज की बड़ी बहन हरसिमरन मनचंदा ने 11 सितंबर को लाजपत नगर थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। 16 सितंबर को दिल्ली पुलिस के माध्यम से परिवार को पता चला कि गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवराज सिंह शव बरामद हुआ था। बादशाहपुर थाने के जांच अधिकारी ने शव की तस्वीर और अन्य विवरण जिप नेट पोर्टल पर अपलोड किए थे। तस्वीर और शव के पास मिले सामान के आधार पर परिजनों ने युवराज की पहचान की।

मानव तस्करी मामले में 8 बांग्लादेशियों समेत 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा

हैदराबाद। एनआईए की विशेष अदालत ने 2019 के एक बड़े मानव तस्करी के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साल 2019 के एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में 8 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने यह सख्त फैसला 17 सितंबर 2026 को सुनाया। कोर्ट के इस कदम को सरहद पार से होने वाले संगठित अपराधों और इंसानों की तस्करी पर कड़ा प्रहार है। यह गंभीर मामला साल 2019 में सामने आया था। इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी की गई थी। जांच में यह बात साबित हुई कि इन पीड़ित महिलाओं को अवैध तरीके से सीमा पार कराकर भारत लाया गया था, जिसके बाद उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति के काले धंधे में धकेल दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। इसी के आधार पर अब 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी गई है, जिनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक हैं।

हनीमून पर गए कपल के साथ बड़ा हादसा, बारबेक्यू का लुत्फ उठा रही दुल्हन झुलसी

सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ पर हनीमून मनाने पहुंचे नवविवाहित दंपती के साथ बारबेक्यू बनाते समय हादसा हो गया। जानकारी मिली है कि वह दंपत्ती उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा बाजार क्षेत्र की निवासी हैं। जानकारी मिली है कि दंपति दार्जिलिंग के कर्सियांग स्थित सिटोंग के एक होमस्टे में ठहरे थे। 13 सितंबर की रात होमस्टे में बारबेक्यू तैयार करने के दौरान लापरवाही के चलते अचानक हादसा हो गया।

आग की चपेट में आने से नवविवाहित के शरीर के कई हिस्से झुलस गए। हादसे के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

गुरुवार को हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद घटना प्रकाश में आया। पहाड़ी क्षेत्रों में बारबेक्यू या कैंपिंग के दौरान आग के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम व प्रशिक्षण के ही पहाड़ पर होटल वह होमस्टे में बारबेक्यू का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।

अमेरिका ने रोका फलस्तीनी राष्ट्रपति का वीजा

यूएनजीए में भारत समेत 152 देशों का मिला समर्थन; आगे क्या होगा?

संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा नहीं दिया। इसके बाद यूएनजीए में उनके वीडियो लिंक से भाषण का रास्ता खुल गया। वीडियो लिंक के जरिये भाषण की अनुमति वाले प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में किन देशों ने वोट दिया, भारत ने किसका साथ दिया।

भारत ने महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इसमें फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अगले हफ्ते होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो लिंक के जरिये भाषण देने की अनुमति दी गई है। अमेरिका ने अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। यह प्रस्ताव बुधवार को भारी बहुमत से पारित हुआ। इसके पक्ष में 152 वोट पड़े। सिर्फ अमेरिका, इस्राइल और

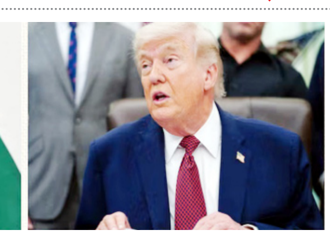

पराग्वे ने इसके खिलाफ वोट किया। चार देशों ने औपचारिक रूप से मतदान से दूरी बनाई।

ईरानी राष्ट्रपति को अमेरिका ने वीजा दिया?

हालांकि, वाशिंगटन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची को उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए वीजा दिया है। यह तब हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब सातवें महीने में पहुंच चुका है। यह दूसरी बार होगा, जब अब्बास महासभा में वीडियो लिंक के जरिये भाषण देंगे। पिछले साल भी वीजा नहीं मिलने के बाद उन्होंने वीडियो लिंक के जरिये भाषण दिया था।

अमेरिका की उप स्थायी प्रतिनिधि टैमी ब्रूस ने अब्बास को वीडियो के जरिये भाषण देने की अनुमति देने से इनकार करने का बचाव किया। उन्होंने फलस्तीन पर आतंकवाद गतिविधियों को छोड़ने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम इस बात पर जोर देना बंद नहीं करेंगे कि फलस्तीनी प्राधिकरण और पीएलओ (फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन जो प्राधिकरण को नियंत्रित करता है) पूरी तरह और बिना किसी शर्त के आतंकवाद को छोड़ें। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। फलस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने इस्राइल के साथ फलस्तीन के अस्तित्व के अधिकार को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दोनों को 'शांति और सुरक्षा में' साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें वीजा देने से इनकार किए जाने का मतलब यह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में मौजूद सबसे बड़ा मुद्दा (फलस्तीनी लोग और उनका नेतृत्व) यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, वे यहां पूरी तरह मौजूद हैं।

राजनीतिक पार्टी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं

तृणमूल के नाम-चिह्न फ्रीज होने पर ऋतब्रत ने ममता पर कसा तंज

कोलकाता। चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर अंतरिम रोक लगाई है। आयोग के इस फैसले पर ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी प्राइवेट कंपनी नहीं होती और उसका कोई वारिस नहीं हो सकता।

तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले पर ऋतब्रत बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि इस आदेश से यह बात साफ हो गई है कि राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट संस्थाओं की तरह नहीं माना जा सकता और न ही उन्हें वंशवादी उत्तराधिकार के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

बनर्जी ने क्या कहा?

पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि यह घटनाक्रम पार्टी नेताओं के लिए हैरानी भरा था, जिन्हें आयोग के फैसले के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि 'प्लेन से उतरते ही हमें पता चला कि सिंबल और नाम को फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि, एक बात साफ है लोकतंत्र में तानाशाही

के लिए कोई जगह नहीं है।

'राजनीतिक पार्टी प्राइवेट कंपनी नहीं होती'

उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग के आज के अंतरिम आदेश से यह साबित हो गया है कि परिवारवादी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। खासकर उस कहानी को देखते हुए जो चुनाव चिह्न और नाम को लेकर चल रही थी। कोई राजनीतिक पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वारिस हो सकता है। आज यह बात साबित हो गई है।'

ऋतब्रत की यह टिप्पणी तब आई जब चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल के नाम और चुनाव चिह्न पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही विरोधी गुटों को विवाद सुलझने तक नए नाम और चिह्न चुनने का निर्देश दिया। आयोग के इस फैसले का पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर काफी असर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम और रेजीनगर, इन दो निर्वाचन क्षेत्रों में 6 अक्तूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उसने अपने पास मौजूद जानकारी पर विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में दो विरोधी गुट हैं। दोनों ही पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं।

आदेश में क्या है?

चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया, 'रिकॉर्ड पर मौजूद सभी जानकारियों पर ठीक से विचार करने के बाद, आयोग का मानना है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में दो विरोधी गुट हैं। एक का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं। दूसरे का नेतृत्व अरूप रॉय कर रहे हैं। दोनों गुट अब खुद को ही पार्टी बता रहे हैं, इसलिए चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग को इस मामले पर ठोस फैसला लेने की जरूरत है।'

दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या, वारदात से पहले आरोपियों ने साथ पी थी शराब

नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. इस जघन्य वारदात को चार लड़कों ने अंजाम दिया है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं.

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात की है, लेकिन इसका खुलासा रविवार सुबह तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने कुशक रोड के पास एक खेत में क्षत-विक्षत अवस्था में शव को देखा. कुत्तों और जंगली जानवरों द्वारा नोचे जाने के कारण शव की हालत बेहद खराब थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए रात भर चले तलाशी अभियान के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया .पकड़े गए आरोपियों में 19 वर्षीय शिवम गणेश और 16 व 17 साल के तीन नाबालिग शामिल हैं.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पीड़िता अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी की तलाश कर रही थी और उनसे अलग रह रही थी. उसकी आरोपियों में से एक 17 वर्षीय लड़के से पहले से जान-पहचान थी.

शुक्रवार रात जब वह उस लड़के से मिलने गई, तो उसने सबसे पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने इस घिनौनी हरकत की शिकायत पुलिस से करने की धमकी दी, तो घबराए आरोपी ने अपने तीन अन्य दोस्तों को मौके पर बुला लिया. शराब के नशे में धुत इन लड़कों ने लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद वे उसे एक खेत में ले गए, जहां उन्होंने चाकू से उस पर कई वार किए और मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पत्तों और कीचड़ के नीचे छिपाने की कोशिश की और मौके से भाग निकले. मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव पाए गए हैं.

शुरूआत में शव की शिनाख्त करना जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि शव तेजी से सड़ चुका था और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था. एसीपी लोकेश्वरन आर और एसीपी रविंदर अहलावत के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला. इसी दौरान अपराध के समय इलाके में एक संदिग्ध टेम्पो घूमता हुआ नजर आया. पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ और फुटेज के विश्लेषण के जरिए टेम्पो का सुराग खोज निकाला, जो स्वरूप नगर की खड्डा कॉलोनी में मिला. टेम्पो चालक से पूछताछ में पता चला कि उसका 17 वर्षीय छोटा भाई अक्सर उस गाड़ी को चलाता है. इसी अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को दबोच लिया. जांच टीम ने वारदात में इस्तेमाल किए गए दोनों चाकू और आरोपियों के कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

अब ईरान को मुंहतोड़ जवाब देगा सऊदी ?, अमेरिका ने 48 एडवांस एफ-35 फाइटर जेट की बिक्री को दी मंजूरी

सऊदी। अमेरिका ईरान की जंग में सऊदी अरब भी निशाना बन रहा है. ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी बेस से हमले शुरू किए थे जो अब सऊदी के बाकी हिस्सों में पहुंच गए हैं.

अमेरिका की मदद का आरोप लगाकर ईरान और हूती लगातार सऊदी पर हमला कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिका ने सऊदी को बड़ी ताकत दी है. अब डील के तहत जल्द ही सऊदी को 48 48 ऋ35 फाइटर जेट मिलेंगे. अमेरिका ने इसकी बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को सऊदी अरब को 48 एफ-35 लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान बेचने की संभावित मंजूरी दे दी. इस सौदे में विमानों के साथ जरूरी उपकरण भी शामिल हैं. पूरे सौदे की अनुमानित कीमत करीब 24.3 अरब अमेरिकी डॉलर है. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, इस संभावित सौदे में पारंपरिक तरीके से उड़ान भरने और उतरने वाले 48 एफ-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं. इसके साथ 49 प्रैट एंड व्हिटनी एफ135-पीडब्ल्यू-100 इंजन भी दिए

जाएंगे. इनमें 48 इंजन विमानों में लगाए जाएंगे, जबकि एक इंजन अतिरिक्त रखा जाएगा.

पैकेज में होंगे ये उपकरण

इस पैकेज में सुरक्षित संचार और सटीक नेविगेशन के लिए जरूरी उपकरण भी शामिल हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जुड़े सिस्टम, विमान और हथियारों के लिए जरूरी सामान, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग उपकरण, सिमुलेटर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी दस्तावेज और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सहायता भी दी जाएगी.

ईरान के बढ़ी मुश्किलें

सऊदी अरब को 48 एफ-35 लड़ाकू विमान मिलने से खाड़ी क्षेत्र में उसकी हवाई सुरक्षा और सैन्य क्षमताओं में बड़ा बदलाव आ सकता है. पांचवीं पीढ़ी के ये स्टील्थ विमान रडार से बचने और निगरानी के साथ-साथ सटीक हमले करने में सक्षम हैं. इससे सऊदी अरब ईरान या उसके समर्थक गुटों की ओर से होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर सकेगा. हालांकि, एफ-35 के सॉफ्टवेयर और हथियारों से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं पर अमेरिकी नियंत्रण बना रहेगा. इसके बावजूद, इस सौदे से खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब की सैन्य क्षमता और रणनीतिक भूमिका बढ़ सकती है.

24.3 अरब डॉलर है लागत

रियाद में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए डील की पुष्टि की. कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब को ऋ35 लाइटनिंग क्क्रजॉइंट स्ट्राइक फाइटर और उससे जुड़े उपकरण बेचने की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 24.3 अरब डॉलर है. कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी. इससे खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति लाने वाले एक प्रमुख गैर-ठअळड सहयोगी देश की सुरक्षा मजबूत होगी.

महत्वपूर्ण ख़बर

सागर सहित पूरे बुंदेलखंड के विकास को नई गति देने में जुटी सरकार

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को ह्यकृषक कल्याण वर्षह्ण के रूप में मना रही है। इसके तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन तकनीक, सिंचाई सुविधाओं सहित कृषि विकास से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि खेती को लाभ का माध्यम बनाने के साथ किसान आय के अन्य स्रोतों को भी मजबूत किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर सागर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़कर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसान कल्याण वर्ष के तहत भगवान बलराम और अन्नदाताओं को समर्पित है।

एमपी के हाइवे होंगे स्मार्ट, स्ट्रीट लाइटें अब कंट्रोल रूम से होंगी संचालित; खराबी की तुरंत मिलेगी सूचना

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे की स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट किया जाएगा। नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) के निर्देशों के पालन में अब ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, रीवा, रतलाम, सागर, उज्जैन और विदिशा जैसे शहरों से गुजरने वाले नेशनल हाइवे में नया केंद्रीयकृत स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगने जा रहा है।

अभी तक सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ये लाइटें बंद चालू होती हैं। खराब होने पर इनकी जानकारी भी तभी लग पाती है, जब पेट्रोलिंग वाहन पहुंचते हैं। अब नए सिस्टम से इन लाइटों को रिमोट के माध्यम से बंद व चालू किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रत्येक लाइट केंद्रीय नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) के दायरे में रहेगी। जैसे ही कोई स्ट्रीट लाइट बंद होगी, वह कंट्रोल रूम में पैनल पर नजर आने लगेगी।

सीसीएमएस का वेब आधारित केंद्रीय सर्वर सभी कारिडोर की लाइटों का डेटा लेकर उसे सुरक्षित रखेगा। सिस्टम में नक्शे पर लोकेशन के साथ हर लाइट की स्थिति एक मैप पर देखी जा सकेगी। प्रत्येक कारिडोर पर स्ट्रीट लाइटों को अलग-अलग कंट्रोल बाक्स से जोड़ा जाएगा।

यही बाक्स स्ट्रीट लाइट खराब होने की सूचना लोकेशन के साथ

कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा, जिससे मैप पर स्ट्रीट लाइट बुझी नजर आएगी। सूचना पहुंचाने के लिए 5जी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि तेज गति से डेटा शेयर हो सके। इसके लिए एनएचएआइ के भोपाल स्थित रीजनल कार्यालय से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें चयनित एजेंसी को ये सिस्टम तैयार करने के साथ ही पांच साल तक उसका रखरखाव भी करना होगा।

बिजली की खपत पर भी नजर

हर सीसीएमएस फीडर पैनल में थ्री-फेज ऊर्जा मीटर लगाया जाएगा। इससे वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, ऊर्जा खपत और लाइटों के संचालन से जुड़े आंकड़े रिकार्ड किए जा सकेंगे। सिस्टम विद्युत आपूर्ति बाधित होने, वोल्टेज या करंट में गड़बड़ी, फीडर ट्रिप होने और अन्य तकनीकी समस्याओं की जानकारी भी देगा। नेटवर्क फेल होने या तकनीकी गड़बड़ी के बावजूद स्ट्रीट लाइटें संचालित होती रहेंगी। सीसीएमएस में स्वतंत्र हार्डवेयर टाइमर का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा पावर फेलियर के दौरान सिस्टम की रियल टाइम क्लाक और इवेंट लाग का बैकअप भी रहेगा।

मुख्यालय के केंद्रीय सर्वर से जुड़ेगा सिस्टम

इस सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया है। इसमें हेकिंग डिटेक्शन, सेल्फ-हीलिंग मैकेनिज्म और फेल-सेफ आपरेशन का प्रविधान है। सिस्टम को एनएचएआइ के केंद्रीय सर्वर से सुरक्षित माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे केंद्रीय स्तर पर निगरानी, रिपोर्टिंग और डेटा मैनेजमेंट किया जा सकेगा। स्ट्रीट लाइटिंग में खराबी या संचार व्यवस्था बाधित होने पर एजेंसी को अधिकतम 48 घंटे में सिस्टम बहाल करना होगा।

स्ट्रीट लाइट की हो सकेगी रियल टाइम निगरानी

प्रदेश के हाइवे और एक्सप्रेस वे की स्ट्रीट लाइटों को सीसीएमएस सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए हमने टेंडर जारी किए हैं। सीसीएमएस से जुड़ने के बाद प्रत्येक स्ट्रीट लाइट की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी।

अजय कुमार स्वामी,
जनरल मैनेजर एनएचएआइ
भोपाल

इंदौर में बढ़ रही पोर्नोग्राफी की लत

दो साल में मामले पांच गुना; युवा ही नहीं 50-60 साल के बुजुर्ग भी शिकार

इंदौर। आज के दौर में आसान इंटरनेट, स्मार्टफोन की पहुंच और जिंदगी का बढ़ता खालीपन मिलकर समाज में एक नई और खतरनाक मानसिक बीमारी को जन्म दे रहे हैं। इंदौर शहर में पोर्नोग्राफी (अश्लील सामग्री) की लत के मामले पिछले दो सालों में करीब पांच गुना तक बढ़ गए हैं।

चिंताजनक बात यह है कि इस गंभीर लत के शिकार केवल युवा या किशोर ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि 50 से 60 साल की उम्र के बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में हैं। मनोचिकित्सकों के पास लगातार पहुंच रहे नए मामले इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि यह लत अब एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन चुकी है।

हर महीने सामने आ रहे 10 से 12 नए मामले

इंदौर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. राहुल माथुर का कहना है कि यह आंकड़े उनके क्लीनिक के अनुभवों पर आधारित हैं। एक समय था जब महीने भर में मुश्किल से एक या दो मरीज इस लत का इलाज कराने पहुंचते थे, लेकिन अब यह संख्या छलांग लगाकर 10 से 12 तक पहुंच गई है। इस लत के पीछे केवल आसान इंटरनेट ही जिम्मेदार नहीं है। रिश्तों में बढ़ता तनाव और इंसान का अकेलापन भी इसका बहुत बड़ा कारण है।

बुजुर्गों में भी हावी हो रही इंटरनेट की लत

मनोचिकित्सक डॉ. रामगुलाम राजदान के मुताबिक, सिर्फ शहरी लोग ही नहीं बल्कि ग्रामीण परिवेश के बुजुर्ग भी इस अजीबोगरीब समस्या का शिकार हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान घरों में रहने के कारण बुजुर्गों में खाली वक्त बिताने के लिए मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग की जो आदत पड़ी थी, वह अब तेजी से एक नकारात्मक लत में तब्दील हो गई है।

इस लत के गंभीर परिणाम कुछ व्यक्तिगत मामलों से भी समझे जा सकते हैं। खुड़ैल के रहने वाले एक 52 वर्षीय व्यक्ति (जो पहले चौकीदार थे) ने साल 2020 में अपनी जमीन बेची। बड़ी रकम हाथ आने के बाद उन्होंने काम-काज छोड़ दिया। इसी खाली समय में उन्होंने मोबाइल का सहारा लिया और धीरे-धीरे इंटरनेट से होते हुए उन्हें पोर्न देखने की ऐसी लत लगी कि परिवार वालों को थक-हारकर उन्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। वहीं, इंदौर के ही एक 26 वर्षीय युवक को भी अपनी पोर्न देखने की पुरानी लत के चलते शादी के तुरंत बाद भारी दांपत्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी लत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट तक पहुंच गया था। वैवाहिक जीवन खराब होने की कगार पर पहुंचने के बाद अब उसकी काउंसलिंग की जा रही है।

सिर्फ 10-15% कंटेंट ही स्कैन कर पाती हैं एजेंसियां

इस ऑनलाइन जंजाल की भयावहता पर स्टेट साइबर सेल के एसपी प्रणय नागवंशी बताते हैं कि इंटरनेट पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट का जाल इतना विशाल है कि जांच एजेंसियां अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कुल कंटेंट का सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही स्कैन कर पाती हैं।

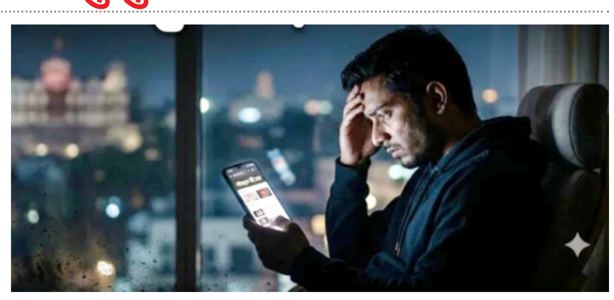

सिर्फ अकाउंट ब्लॉक करना काफी नहीं: साइबर एक्सपर्ट

साइबर सुरक्षा सलाहकार चातक वाजपेयी का मानना है कि इस डिजिटल बीमारी को रोकने के लिए सोशल मीडिया से सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट हटा देना या किसी एक अकाउंट को ब्लॉक कर देना कतई काफी नहीं है। आज के एआई आधारित सिस्टम के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक कंटेंट परोसने वाले मूल अकाउंट, उसके विज्ञापनदाताओं, पेमेंट ट्रेल (पैसे के लेन-देन), मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस और बाहरी वेबसाइटों की पूरी जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, तब तक इस पर पूरी तरह लगाम लगाना संभव नहीं है।

राजीव गांधी हत्याकांड का हवाला देकर राहुल की सुरक्षा को लेकर एमपी पुलिस ने थोपीं 31 शर्तें

इंदौर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हुई हत्या का हवाला देकर पुलिस ने राहुल गांधी के 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले ह्यछात्रों की गूंजह्ण कार्यक्रम को लेकर आयोजकों के सामने 31 शर्तें रखी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी निदेर्शों में पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित वर्मा आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है।

पुलिस ने आयोजकों से कार्यक्रम में आने वालों की वास्तविक संख्या बताने के साथ यह भी पूछा है कि किस जिले या कॉलेज से कितने लोग आ रहे हैं। कितने निजी वाहनों से आएंगे और कितने बस या रेल से। पुलिस ने वाहनों के नंबर और चालकों के मोबाइल नंबर भी मांगे हैं। पुलिस की इन शर्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये शर्तें सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं। आयोजक अपेक्षित उपस्थिति की वास्तविक संख्या लिखित शपथ-पत्र पर दें। इसमें पुरुष एवं महिला/छात्राओं की अलग–अलग संख्या मांगे। स्थल की क्षमता से अधिक संख्या की अनुमति नहीं होगी तथा स्वीकृत क्षमता भरने पर प्रवेश रोकने का अधिकार पुलिस के पास सुरक्षित रहेगा।

परिवहन का विवरण प्रस्तुत किया जाए। किस जिले/तहसील/महाविद्यालय से कितने व्यक्ति आ रहे हैं, कितने बस से, कितने निजी वाहन से एवं कितने रेल से, बसों की कुल संख्या, वाहन क्रमांक, चालक का नाम एवं मोबाइल सहित सूची, तथा प्रत्येक समूह का आगमन मार्ग, अनुमानित समय एवं निर्धारित पार्किंग पाकिट पूर्व में तय किया जाएगा।

- स्थल का स्केल-मैप प्रस्तुत किया जाए। इसमें मंच, डी-एरिया, सेक्टर विभाजन, गैंगवे, होल्ड-अप एरिया, प्रवेश एवं निकास द्वार, आपातकालीन कारिडोर तथा पार्किंग स्पष्ट रूप से अंकित हों।
- भीड़ को दो हजार व्यक्ति क्षमता के पृथक सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर का रंग-कोड, क्रमांक एवं नामित सेक्टर प्रभारी होगा।
- प्रत्येक सेक्टर के बीच पर्याप्त चौड़ाई का मार्ग हो। प्रवेश द्वार से मंच तक छह मीटर चौड़ा आपातकालीन कारिडोर खाली रखना होगा।
- मंच के सामने 25 से 30 फीट का खाली डी-एरिया रहेगा। इसमें सिर्फ सुरक्षाकर्मी रहेंगे।
- मंचस्थ अतिथि, मंचस्थ छात्र, स्वयंसेवक एवं मीडिया के लिए पृथक-पृथक होल्ड-अप एरिया बनाए जाएंगे।
- डोम/पंडाल अग्निरोधी सामग्री से बनेगा। इसका प्रमाण पत्र देना होगा।
- कम से कम छह प्रवेश एवं आठ निकास द्वार बनाने होंगे।
- प्रत्येक प्रवेश द्वार पर महिलाओं के लिए पृथक पदार्युक्त फ्रिस्किंग एनक्लोजर तथा पर्याप्त महिला सुरक्षाकर्मी/स्वयंसेवक रहेंगी।
- कम से कम 1500 स्वयंसेवक, जिनमें कम से कम 500 महिलाएं होंगी, सेक्टरवार तैनात करने होंगे।
- ड्रोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल पुलिस का अधिकृत ड्रोन प्रयुक्त होगा।

कार्यक्रम में कोई आपत्तिजनक अथवा उत्तेजक चित्र, बैनर, पोस्टर या होर्डिंग प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। किसी धर्म, जाति, समुदाय अथवा राजनीतिक/गैर-राजनीतिक संगठन के विरुद्ध भड़काऊ या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी। पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराकर पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी।

शिप्रा तट और महाकाल महालोक में 33.27 लाख दीये एकसाथ किये गये प्रज्ज्वलित, बना वर्ल्ड रिकार्ड

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर आशीर्वाद दीया जलाकर सेवा संकल्प अभियान का पूरे प्रदेश में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के सभी जिलों और 845 आईकॉनिक प्लेस में 3 करोड़ 55 लाख दीये एकसाथ जलाये गये। सिर्फ उज्जैन में ही 33 लाख 27 हजार दीये एक साथ प्रज्ज्वलित कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया। उज्जैन के शिप्रा के रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंघी ने उज्जैनवासियों के साथ मिलकर दीप प्रज्ज्वलित किये। उज्जैन में शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों सहित महाकाल लोक में सायं 7 बजे सायरन बजने के साथ सभी लोगों ने मिलकर दीप जलाये और प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंघी शिप्रा आरती में शामिल हुए और मां शिप्रा की आराधना कर प्रदेशवासियों की सुख–समृद्धि की कामना की। उज्जैन के शिप्रा घाटों पर सायरन की आवाज के साथ ही आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित हुआ वैसे ही कार्यक्रम के अतिथि, 25 हजार से अधिक वॉलिंटियर्स, श्रद्धालु और नागरिकों ने एक साथ दीयों का प्रज्ज्वलन प्रारंभ किया। लाखों दीप प्रज्ज्वलन के साथ घाट घाट जगमग हो उठे। प्रज्ज्वलित हुए लाखों दीप मानों प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस पर उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र भक्ति की सेवा के लिए किये गए 25 वर्षों के कार्यों के प्रति आदर और स्नेह की रोशनी फैला रहे थे।

पीएम श्री मोदी वह सब काम कर रहे हैं, जो राम राज्य में होता था : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्षो में वह सब काम किया है जो रामराज में होता था। उन्होंने निरंतर कठिन मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अपने आराम की भी चिंता नहीं की और 25 वर्षों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिनके द्वारा दी गई सौगातें लंबे समय तक याद रहेगी। वे गरीब आदमी को रहने के लिए मकान और जीवन यापन के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का पुण्य कार्य कर रहे है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात आज उज्जैन में रामघाट शिप्रा तट पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित दीपोत्सव समारोह में कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और वह आने वाले अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष का गौरवशाली कार्यकाल पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आज मध्यप्रदेश में हमने उनके सपने को साकार करने का प्रयास किया है। अब प्रदेश के सभी गांव में 50 लाख से अधिक लोगों को जिनके मकान खेत खलिहान के पट्टे हैं, उनकी रजिस्ट्री करने का अभियान चलाया चलाया जा रहा है। यह नि:शुल्क रजिस्ट्री की सौगात मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन दिवस मनाया।

हम उम्मीद करते हैं कि आज का दीपोत्सव सबके जीवन से अंधकार मिटाए। मानवता के लिए जियो और जीने दो की सनातन धर्म की धारणा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मजबूत हुई है और भारत एक स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने कहा कि वे उज्जैन की देवभूमि को प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 50 लाख लोगों को जमीन का हक दिलाने का काम किया है। यह काम प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2020 में शुरू किया था जिसको आज पूर्णता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रदान की गई है। अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है और सनातन धर्म का परचम लहराया है। उन्होंने गरीब लोगों के जीवन में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही लोगों को आशियाना मिला है और गांव की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2014 में सत्ता परिवर्तन नहीं सोच का परिवर्तन हुआ है, जो आज परीलक्षित हो रहा है।

मोमोज की दुकान वाले ने शराब के लिए नहीं दिए रुपये, बदमाशों ने उस पर डाला खौलता तेल

इंदौर। बजरंग नगर में बुधवार को बदमाशों ने उत्पात मचाया। मोमोज दुकान संचालक के साथ मारपीट की और खौलता तेल उड़ेल दिया।

हीरानगर पुलिस के अनुसार आरोपित शुभम पंडित, अमन गेले और उसके दो साथी फरियादी समीर मोरे से रुपयों की मांग कर रहे थे। एक अन्य दुकान संचालक हर्ष गणगोरे को भी धमकाया गया।

आरोपियों ने रुपये न देने पर चाकू निकाला और हर्ष पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने कढ़ाई से गर्म तेल उड़ेल दिया। इससे समीर की पीठ, हाथ आदि झुलस गए। पुलिस ने दो के खिलाफ नामजद कायमी की। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था।

उस समय दुकान पर बच्चे और युवतियां भी मौजूद थीं। बदमाशों ने दुकान में रखा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया और चाकू लहराए। काफी देर तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची।

इससे वहां अफरातफरी मच गई और लोग डरकर अपने घरों में चले गए।

स्कूटर टकराने पर विवाद, बुजुर्ग सहित तीन लोगों से मारपीट

भंवरकुआं क्षेत्र में बुधवार रात स्कूटर टकराने पर विवाद हो गया। युवकों ने बुजुर्ग सहित तीन लोगों के साथ मारपीट कर दी। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ब्रह्मपुरी कालोनी निवासी 66 वर्षीय संजय हार्डिया की शिकायत पर निखार निवासी तेजपुर गड़बड़ी, चेतन परमार और महावेंद्र पगारे निवासी तेजपुर गड़बड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार घटना ब्रह्मपुरी कॉलोनी (भोला राम उस्ताद मार्ग) की है। हार्डिया किराना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसके बाद वह भाई विनोद हार्डिया से बात करने लगे। इसी दौरान स्कूटर से गुजर रहे युवकों ने वहां खड़े कृष्णा को स्कूटर से टक्कर मार दी। आरोपियों ने कृष्णा के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाव करने पर आरोपितों ने संजय और विनोद पर भी हमला कर दिया। विनोद के पेट और हाथ में चाकू से वार करने का आरोप है। इस विवाद में उसकी सोने की चेन भी टूटकर गिर गई। काफी देर तक मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।

आज से 10 नई ई-बसों का तोहफा, 4 नए रूट के साथ कनेक्ट होंगे शहर के प्रमुख अस्पताल और मेट्रो स्टेशन

भोपाल। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को विस्तार देते हुए शुक्रवार से 10 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। इसके साथ शहर में संचालित ई-बसों की संख्या 30 से बढ़कर 40 हो जाएगी। शुक्रवार से नई बसों के संचालन के बाद चार रूटों पर ई-बस सेवा उपलब्ध होगी।

नए रूटों में शहर के प्रमुख अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बाजार, मेट्रो स्टेशन और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ा गया है। इनमें बैरागढ़ से सलैया, कोच फैक्ट्री से कोलार रोड, बैरागढ़ से आइएसबीटी और बैरागढ़ से मंडीदीप तक बसें चलेंगी।

दिव्यांग यात्रियों का भी रखा गया है ख्याल

इन बसों में दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बसों में चढ़ने-उतरने के लिए हाइड्रोलिक डोर की सुविधा है। इससे ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर पर आने वाले यात्री आसानी से बस में प्रवेश कर सकेंगे। बस के भीतर एक साथ दो व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल खड़ी करने के लिए भी जगह आरक्षित की गई है।

बता दें कि पीएम ई-बस सेवा के तहत कुल 48 ई-बसें शहर में आ चुकी हैं, जो बैरागढ़ स्थित डिपो पर खड़ी हुई हैं। वर्तमान में इनमें से तीन रूटों पर 30 बसें चल रही हैं। शुक्रवार को 10 बसों के और सड़कों पर उतरने के बाद इनकी संख्या 40 हो जाएगी, जो चार रूटों पर चलेंगी।

इन रूटों पर चलेंगी बसें

रूट बी-35: बैरागढ़ से सलैया-चिरायु अस्पताल, बैरागढ़ मार्केट, लालघाटी, कलेक्ट्रेट, हमीदिया अस्पताल, रायल मार्केट, पीर गेट,

कमला पार्क, पालीटेक्निक चौराहा, रोशनपुरा, लिंक रोड नंबर-एक, रेडक्रास अस्पताल, बोर्ड आफिस, एमपी नगर मेट्रो स्टेशन, भाजपा कार्यालय, विट्ठल मार्केट, 12 नंबर, रोहित नगर और बावड़िया चौराहा होते हुए आकृति इको सिटी, सलैया तक बस चलेगी।

रूट बी-36: कोच फैक्ट्री से कोलार रोड- द्वारका नगर, कोच फैक्ट्री, भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म-एक, अशोका गार्डन, प्रभात चौराहा, ओल्ड सुभाष नगर, चेतक ब्रिज, एमपी नगर मेट्रो स्टेशन, भाजपा कार्यालय, विट्ठल मार्केट, मनीषा मार्केट, बंसल अस्पताल, चूनाभट्टी, मंदाकिनी चौराहा, नयापुरा, ललिता नगर और गेहूंखेड़ा होते हुए बैरागढ़ चिचली तक बस जाएगी।

रूट बी-37: बैरागढ़ से आइएसबीटी- बैरागढ़ मार्केट, लालघाटी, कलेक्ट्रेट, हमीदिया अस्पताल, शाहजहांनाबाद, नादरा बस स्टैंड, भोपाल स्टेशन प्लेटफार्म-छह, जहांगीराबाद, पीएचक्यू, मिंटो हाल, बिड़ला मंदिर, वल्लभ भवन, विंध्याचल, जिला न्यायालय, चेतक ब्रिज होते हुए आइएसबीटी तक संचालन होगा।

रूट बी-38: बैरागढ़ से मंडीदीप- यह सबसे लंबा रूट होगा। बस बैरागढ़, लालघाटी, कलेक्ट्रेट, रायल मार्केट, नादरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहांगीराबाद, पीएचक्यू, बिड़ला मंदिर, वल्लभ भवन, बोर्ड आफिस, चेतक ब्रिज और आइएसबीटी से रानी कमलापति स्टेशन जाएगी। इसके बाद बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, बागसेवनिया, आशिमा माल, मिसरोद, 11 मील, इंडस टाउन, चिनार ड्रीम सिटी, सतलापुर जोड़ होते हुए एचईजी मंडीदीप तक पहुंचेगी।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के आयोजन स्थल में हो सकता है बदलाव, रांची से छिनेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच की मेजबानी

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) की मेजबानी इस बार भारत करेगा। दोनों टीमों के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज अगले साल 21 जनवरी से शुरू होगी और 27 फरवरी तक चलेगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, सीरीज का पहला टेस्ट नागपुर, दूसरा चेन्नई, तीसरा गुवाहाटी, चौथा रांची और पांचवां एवं आखिरी टेस्ट अहमदाबाद में खेला जाना है।

हालांकि, अब सीरीज शुरू होने से पहले ही मुकाबले के आयोजन स्थल में बदलाव की चर्चा सामने आई है। रांची में प्रस्तावित चौथे टेस्ट को किसी अन्य शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए विशाखापत्तनम हैदराबाद और राजकोट जैसे शहरों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

आयोजन स्थल में क्यों किया जाएगा बदलाव?

रांची के आयोजन स्थल में बदलाव की चर्चा के पीछे मुख्य वजह सर्दियों के दौरान वहां जल्दी सूर्यास्त होना बताई जा रही है। टीम प्रबंधन ने बीसीसीआई के सामने यह मुद्दा उठाया है कि जनवरी-फरवरी के दौरान रांची में सूरज के जल्दी ढालने के कारण शाम जल्दी हो जाती है। ऐसे में टेस्ट मैच के दौरान रोशनी की कमी के कारण खेल के समय में कटौती हो सकती है और पांच दिन का मुकाबला निर्धारित समय में पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यह सीरीज भारत के लिए टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में टीम प्रबंधन चाहता है कि मैचों के आयोजन स्थल और समय का चयन इस तरह किया जाए, जिससे पांचों टेस्ट में अधिक से अधिक खेल हो सके। सीरीज के अन्य आयोजन स्थलों को लेकर फिलहाल किसी बदलाव की चर्चा नहीं है। नागपुर और अहमदाबाद देश के पश्चिमी हिस्से में, चेन्नई दक्षिण भारत में, जबकि गुवाहाटी और रांची पूर्वी हिस्से में स्थित हैं।

गुवाहाटी भी चर्चा के केंद्र में

रांची में शाम जल्दी होने की समस्या को देखते हुए उसके मुकाबले को किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं, गुवाहाटी को लेकर भी समय में मामूली बदलाव संभव है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया असम से हैं और गुवाहाटी में टेस्ट की मेजबानी का कार्यक्रम फिलहाल बरकरार रहने की संभावना है। हालांकि, वहां दिन की रोशनी का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए मैच सामान्य समय से करीब आधा घंटा पहले शुरू किया जा सकता है। टीम प्रबंधन चाहता है कि उस समय रांची में ठंड होगी इसलिए न ही उस तरह की पिच मिलेगी न ही पूरा मैच होगा। ऐसे में रांची के मैच को दक्षिण और पश्चिम के शहरों में कराए जाने की सिफारिश की गई है।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका की बात करें तो मौजूदा स्थिति में भारत 68 अंकों और 51.52 जीत प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 96 अंकों और 80 जीत प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है। भारत के लिए घरेलू परिस्थितियों में इस सीरीज का परिणाम उसके डब्ल्यूटीसी फाइनल की दावेदारी पर बड़ा असर डाल सकता है।

अभिषेक शर्मा का शतक और संजू सैमसन का धमाका

अफगानिस्तान पर 3-0 की क्लीन स्वीप के ये रहे 5 सबसे बड़े हीरो

नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मैच में हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने तीसरे मैच में पहले बैटिंग करते हुए 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में अफगानी टीम मात्र 94 रनों पर सिमट गई और उन्हें 127 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

भारत के खिलाफ 127 रनों की हार अफगानिस्तान के टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इसके अलावा अब तक अफगानी टीम ने भारत को टी20 फॉर्मेट में नहीं हराया है और टीम इंडिया ने 12 मुकाबले जीत लिए हैं। भारतीय टीम को 3-0 से जीत दिलाने में अभिषेक शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। उनके अलावा भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को सीरीज में जीत दिलाई। आइए आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों को बारे में बताते हैं।

1. अभिषेक शर्मा

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले मैच में भी 82 रनों की पारी खेली थी, जहां वे शतक लगाने से चूक गए थे। इसके बाद दूसरे मैच में शर्मा ने 39 रन बनाए। गुरुवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में अभिषेक ने 108 रनों की पारी खेली। वे सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां बाएं हाथ के बैटर ने 3 मैचों में 229 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

2. संजू सैमसन

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पहले मैच में फ्लॉप हो गए थे, जिसके बाद उनकी फॉर्म पर सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि, दूसरे मैच में उन्होंने 20 गेंदों पर ही अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद तीसरे मुकाबले में भी सैमसन का बल्ला चला और उन्होंने अर्धशतक लगाया। सैमसन ने पूरी सीरीज में 117 रन बनाए और दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

3. नितीश कुमार रेड्डी

ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने भी टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रेड्डी ने पहले मैच में तो खराब गेंदबाजी की लेकिन दूसरे और फिर तीसरे मैच में उन्होंने तीन-तीन विकेट लिए। वे बल्ले से भले ही अपना जलाव नहीं दिखा सके लेकिन गेंद के साथ कुल 6 विकेट लिए। वे सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे।

4. अर्शदीप सिंह

तेज गेंदबाद अर्शदीप सिंह को तीसरे मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि, उन्होंने इस सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की। दो मैचों में अर्शदीप के नाम 5 विकेट रहे। वे एक मैच कम खेले लेकिन इसके बावजूद दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

5. ईशान किशन

ईशान किशन तीसरे टी20 मैच में अपना कमाल नहीं दिखा सके। वे 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। हालांकि, पहले दो मैचों में टीम इंडिया की जीत में किशन ने अहम भूमिका निभाई। ईशान ने सीरीज में कुल 90 रन बनाए और भारत के लिए सीरीज में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

खराब पिच के लिए लीसेस्टरशायर पर जुर्माना

लंदन। लीसेस्टरशायर ने अपने मैदान की खराब पिच के कारणों में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की आत्मकथा के फिल्मांकन की अनुमति देने को भी शामिल किया था, लेकिन अनुशासनात्मक पैनल ने इस दलील को खारिज करते हुए पिच नियमों के उल्लंघन के लिए काउंटी क्लब पर 27 अंक का जुमार्ना लगाया है। लीसेस्टरशायर के पास क्रिकेट अनुशासन पैनल के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय है। इस फैसले के बाद क्लब डिवीजन एक से ह्यरेलीगेशनह्न (निचली लीग में खिसकना) के खतरे के करीब पहुंच गया है। पैनल ने खराब पिच को लेकर क्रिकेट नियामक की शिकायत को बरकरार रखा। उसने ग्लेमोर्गन के खिलाफ 20 से 23 अगस्त के बीच ग्रेस रोड में 42 रन की जीत से मिले 19 अंक काट लिए और आठ अंक का अतिरिक्त जुमार्ना भी लगाया। इसके अलावा क्लब पर 5,000 पाउंड का जुमार्ना भी लगाया गया। ग्रेस रोड के मुख्य मैदानकर्मी कैलम लेविन ने क्रिकेट नियामक को बताया कि ग्लेमोर्गन के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार की गई पिच कई ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित हुई जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। लेविन ने क्रिकेट नियामक को बताया, इस बार यह इस्तेमाल की हुई पिच थी। हमने 10 सप्ताह पहले इस पर दो टी20 मैच खेले थे। मैच से पहले कई ऐसी परिस्थितियां थीं जो मेरे नियंत्रण से बाहर थीं, जैसे तापमान 35 डिग्री था। मैच (ग्लेमोर्गन के खिलाफ) से चार दिन पहले हमारे यहां बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और मुझे पिच पर काम करने की अनुमति नहीं थी। मुझे इसे ढकने की भी अनुमति नहीं थी।

जिम्बाब्वे के टावेंगवा मुखुहलानी बने नए उपाध्यक्ष, इमरान ख्वाजा की ली जगह; अध्यक्ष जय शाह ने दी बधाई

दुबई। टावेंगवा मुखुहलानी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह नवंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। मुखुहलानी इस समय जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन हैं और आईसीसी बोर्ड में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इमरान ख्वाजा के पद छोड़ने के बाद यह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। मुखुहलानी आईसीसी की फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स (एफ एंड सीए) कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा, वह आईसीसी की एचआर और रेमुनरेशन कमेटी के प्रमुख भी हैं। अब उपाध्यक्ष का पद संभालकर वह आईसीसी के इस अहम पद पर पहुंचने वाले जिम्बाब्वे के पहले व्यक्ति बने हैं।

उनकी नियुक्ति अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ मिलकर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की सह-मेजबानी करेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट में लीडरशिप अनुभव और क्षेत्रीय जानकारी के दम पर मुखुहलानी अहम मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आईसीसी 24 साल में पहली बार इस बड़े टूनार्मेंट को अफ्रीका में वापस ला रहा है।

मुखुहलानी ने अपनी नियुक्ति पर कहा, मेरे साथी आईसीसी बोर्ड डायरेक्टरों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और आईसीसी के उपाध्यक्ष के तौर पर सेवा करने का मौका मिलने के लिए आभारी हूं। मैं हमारे चेयरमैन जय शाह के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, जिनकी लीडरशिप, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा ने आईसीसी को एक स्पष्ट मकसद दिया है, जिसमें क्रिकेट को बढ़ाने, हमारे सदस्यों के लिए मौके बनाने और नए दर्शकों और बाजारों तक पहुंचने पर खास ध्यान दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, क्रिकेट एक रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहा है, खासकर ओलंपिक खेलों में इसकी वापसी और लगातार वैश्विक विस्तार के साथ। मैं अपनी साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और विश्व स्तर पर क्रिकेट के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने में हमारे चेयरमैन जय शाह और साथी बोर्ड डायरेक्टरों का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूं।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, मैं आईसीसी के उपाध्यक्ष के तौर पर चुने जाने पर टावेंगवा मुखुहलानी को दिल से बधाई देता हूं। क्रिकेट प्रशासन में उनका अनुभव, वैश्विक खेल की समझ और इसके विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आईसीसी बोर्ड के लिए बहुत कीमती होगी। टावेंगवा ने अपने साथी डायरेक्टर्स का भरोसा जीता है।

कारोबार

द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में हरियाली; सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 23,300 के पार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरूआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख रहा। सुबह 9:23 बजे तक निफ्टी 50 में 0.20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो 23,315.80 पर पहुंच गया। वहीं, बीएसई सेंसेक्स 0.22 फीसदी बढ़कर 74,474.19 पर कारोबार कर रहा था।

बाजार में यह बढ़त कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण देखी गई। हालिया नुकसान के बाद निवेशकों ने सस्ते में खरीदारी की। हालांकि, मध्य पूर्व में जारी तनाव ने बाजार की तेजी पर कुछ अंकुश लगाया। घरेलू आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की मजबूत मांग भी बढ़त को सीमित कर रही थी। कुल 16 प्रमुख क्षेत्रों में से 15 ने बढ़त दर्ज की। व्यापक स्मॉल-कैप और मिड-कैप सूचकांकों में प्रत्येक में 0.2 फीसदी की वृद्धि हुई। इंडिगो और इटर्नल जैसे शेयरों ने बाजार की बढ़त का नेतृत्व किया। दूसरी ओर, टाटा समूह के अधिकांश शेयरों में गिरावट देखी गई।

बाजार में तेजी के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार में उछाल का एक प्रमुख कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी थी। निवेशकों ने हाल की गिरावट के बाद सस्ते में खरीदारी का अवसर देखा। हालांकि, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने बाजार की तेजी को कुछ हद तक धीमा किया। घरेलू आईपीओ की मजबूत मांग भी बाजार की बढ़त को पूरी तरह से खुलने नहीं दे रही थी।

वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा और किन शेयरों में हलचल दिखी?

वैश्विक बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला। जापान का टॉपिक्स 0.4 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.1 फीसदी गिरा। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में भी 0.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, हांगकांग का हैंग सेंग 0.7 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 1 फीसदी बढ़ा। टाटा समूह के टीसीएस, टाटा मोटर्स पीवी, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा केमिकल्स के शेयरों में 2.5 फीसदी से 7 फीसदी तक की गिरावट आई।

यूपीआई पर एमडीआर शुल्क: आखिर कौन चुकाएगा डिजिटल भुगतान की कीमत?

नई दिल्ली। कपड़ा व्यापारी हो, जयपुर का सुपरमार्केट संचालक हो या किसी हाईवे का पेट्रोल पंप मालिक...तीनों का कारोबार अलग-अलग है, लेकिन चिंता एक समान है। 15 अक्तूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर लगने वाले एमडीआर शुल्क के बाद उन्हें अपने मुनाफे, कीमतों और भुगतान का नया हिसाब लगाना पड़ेगा। नवीन गुप्ता पिछले 11 साल से कानपुर के सीसामऊ बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। पहले ग्राहक नकद देते थे, फिर कार्ड मशीन आई और अब 70 फीसदी भुगतान यूपीआई से होता है। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है लेकिन इस बार उन्हें कपड़ों की बिक्री से ज्यादा चिंता यूपीआई के नए खर्च की है। वह कहते हैं कि अगर 3,000-5,000 रुपये के ज्यादातर बिल यूपीआई से चुकाए जाएंगे और उन पर शुल्क लगेगा, तो या तो उन्हें अपना मार्जिन कम करना होगा या फिर किसी दूसरे तरीके से लागत निकालनी होगी। उनके जैसे लाखों व्यापारी अब यही हिसाब लगा रहे हैं कि डिजिटल भुगतान की सुविधा का खर्च आखिर कौन उठाएगा।

जयपुर के गांधी मार्केट में सुपर स्टोर संचालक रोशनलाल बताते हैं कि उनका मासिक यूपीआई लेनदेन 80 लाख रुपये से ज्यादा है। अगर हर बड़े भुगतान पर अतिरिक्त लागत जुड़ती है तो उन पर एक लाख का बोझ पड़ सकता है। यह चिंता सिर्फ खुदरा कारोबार तक सीमित नहीं है।

अमेरिकी टैरिफ की चुनौती: किन उद्योगों पर ज्यादा दबाव, बचाव का रास्ता कहां?

नई दिल्ली। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का नया दबाव सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि देश की निर्यात रणनीति की बड़ी परीक्षा बन सकता है। अमेरिका भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार है। इंजीनियरिंग सामान, दवा, रत्न-आभूषण, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स तक उद्योगों की कमाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। सबसे बड़ा खतरा केवल अतिरिक्त टैरिफ नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। उद्योग संगठनों व निर्यातकों की नजर अब सरकारी रणनीति पर टिकी है।

टैरिफ से निपटने के 5 बड़े हथियार

- नए एफटीए और बाजार विविधीकरण
- अमेरिका के साथ लगातार व्यापारिक वार्ता
- लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह लागत में कमी
- इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और इंजीनियरिंग में मजबूत बढ़त
- चीन प्लस वन रणनीति से निवेश आकर्षित करना

क्या एफटीए बनेंगे सुरक्षा कवच?

यही वह सवाल है जिस पर उद्योग जगत सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा है। हाल में भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों का दायरा बढ़ाया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अजय श्रीवास्तव ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का विकल्प तुरंत खोजना मुमकिन नहीं, लेकिन जोखिम बांटना संभव है। हालांकि ट्रंप आसानी से ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ेगे, जिसके जरिये दूसरे देशों से रियायतें हासिल की जा सकें।

ब्रोकरेज की कॉल पर नहीं कंपनी के दम पर लगाएं दांव; कोरे डिजिटल पर सेबी की सख्ती

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जब ऊपरी स्तरों पर भारी उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता का माहौल होता है, तब आम निवेशक असमंजस में रहता है कि अपना पैसा कहां सुरक्षित रखे और कहां निवेश कर मुनाफा कमाए। ऐसे दौर में बड़े ब्रोकरेज हाउस अपनी रिसर्च और रिपोर्ट्स जारी कर निवेशकों को राह दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इन पर आंख मूंदकर भरोसा करना कई बार घातक साबित हो सकता है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी हो जाती है।

जीएमआर एयरपोर्ट्स: ब्रोकरेज फर्म मैक्वरी ने इस पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग देते हुए 120 रुपये का टारगेट तय किया है। इंटेलीसिस वेंचर्स के संस्थापक अमित जैन का मानना है कि वर्तमान बाजार मूल्य पर तुरंत खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाव में अभी करीब 10 रुपये की और गिरावट आ सकती है। 85 रुपये के आसपास खरीदारी सुरक्षित रहेगी।

भारतीय स्टेट बैंक : जेफरीज ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर बड़ा भरोसा जताते हुए 1,320 रुपये का तगड़ा टारगेट दिया है। बाजार विशेषज्ञ अमित जैन के अनुसार, एसबीआई का तकनीकी स्ट्रक्चर अभी थोड़ा कमजोर हुआ है और इसमें 880 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मौजूदा भाव पर आक्रामक खरीदारी से बचना चाहिए। किसी के पास पहले से शेयर है, तो वे लोग 1,000 रुपये के आसपास निकलने का सोच सकते हैं।

दालों के राजा कहे जाने वाले अरहर के तेवर एक बार फिर तीखे होने लगे हैं। मानसून की बेरुखी और योहारों से पहले मिलर्स की खरीद और के कारण अरहर के दाम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। केडिया एडवाइजरी के रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक महीने में अरहर की कीमतों में लगभग 10.92 फीसदी और पिछले तीन महीनों में 11.02 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। अखिल भारतीय स्तर पर इसका औसत मण्डी भाव 8,141.25 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ाकर 8,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो बाजार की कीमतों को नीचे गिरने से रोक रहा है।

बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय गड़बड़ियों, फर्जी अधिग्रहण और धन के कथित दुरुपयोग के आरोपों के चलते कोरे डिजिटल लि. और उसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नियामक ने कंपनी, एमडी रवींद्र दोशी, मुख्य वित्तीय अधिकारी कश्मीरा दोशी और सीईओ चैतन्य दोशी को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है।

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को निर्देश दिया है कि वह कोरे डिजिटल को अपने एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड पर जाने की अनुमति न दे। शुरूआती जांच में पाया गया कि कंपनी ने छोटे मंच से मुख्य प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड पूरा दिखाने के उद्देश्य से अपने राजस्व को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। वित्तीय स्थिति बेहतर बताने के लिए खातों में हेरफेर की और तीन सहायक कंपनियों के जरिये 541.3 करोड़ रुपये की आय को गलत तरीके से दर्ज किया। यह इस अवधि में कंपनी की कुल आय का लगभग 73 फीसदी है।

आज की आवश्यकता

सब्जी बगीचा

अच्छे स्वास्थ्य के लिए दैनिक आहार में संतुलित पोषण का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फल एवं सब्जियाँ इसी संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है क्योंकि ये विटामिन, खनिज लवण तथा कार्बोज के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर भी ये जरुरी हैं कि इन फल एवं सब्जियों की नियमित उपलब्धता बनी रहे. इसके लिए घर के पिछवाडें मे पडी जमीन पर खेती करना बहुत ही लाभदायक उपाय हैं। पोषाहार विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित भोजन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल और 300 ग्राम साग–सब्जियों का सेवन करना चाहिए। परन्तु हमारे देश में साग–सब्जियों का वर्तमान उत्पादन स्तर प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति की खपत के हिसाब से मात्र 120 ग्राम है।

सब्जी बगीचा

▸ उपलब्ध स्वच्छ जल के साथ रसोईघर एवं स्नानघर से निकले पानी का उपयोग कर घर के पिछ्वाड़े में उपयोगी साग-सब्जी उगाने की योजना बना सकते हैं।

▸ एकत्रित अनुपयोगी जल का निष्पादन हो सकेगा और उससे होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी।

▸ सीमित क्षेत्र में साग-सब्जी उगाने से घरेलू आवश्यकता की पूर्ति भी हो सकेगी।

▸ सब्जी उत्पादन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं होगी।

अतः यह एक सुरक्षित पद्धति है तथा उत्पादित साग-सब्जी कीटनाशक दवाईयों से भी मुक्त होंगी।

सब्जी बगीचा के लिए स्थल

सब्जी बगीचा के लिए स्थल घर का पिछ्वाड़ा ही होता है जिसे हम लोग बाड़ी भी कहते हैं। यह सुविधाजनक स्थान होता है क्योद्धक परिवार के सदस्य खाली समय में साग-सब्जियों पर ध्यान दे सकते हैं तथा रसोईघर व स्नानघर से निकले पानी आसानी से सब्जी की क्यारी की ओर घुमाया जा सकता है।

सब्जी बगीचा का आकार भूमि की उपलब्धता और व्यक्तियों की संखया पर निर्भर करता है। चार या पाँच व्यक्ति वाले औसत परिवार के लिए 1/20 एकड़ जमीन पर की गई सब्जी की खेती पर्याप्त हो सकती है।

पौधा लगाने के लिए खेत तैयार करना

सर्वप्रथम 30-40 सेंमी की गहराई तक कुदाली या हल की सहायता से जुताई करें। खेत से पत्थर, झाड़ियों एवं बेकार के खर-पतवार को हटा दें। खेत में अच्छे ढंग से निर्मित 100 कि.ग्राम कृमि खाद चारों ओर फैला दें। आवश्यकता के अनुसार 45 सेंमी या 60 सेंमी की दूरी पर मेड़ या क्यारी बनाएँ।

सब्जी बीज की बुआई और पौध रोपण

सीधे बुआई की जाने वाली सब्जी जैसे -भिंडी, पालक एवं लोबिया आदि की बुआई मेड़ या क्यारी बनाकर की जा सकती है। दो पौधे 30 सेंमी की दूरी पर लगाई जानी चाहिए। प्याज, पुदीना एवं धनिया को खेत के मेड़ पर उगाया जा सकता है।प्रतिरोपित फसल, जैसे - टमाटर, बैगन और मिर्ची आदि को एक महीना पूर्व में नर्सरी बेड या टूटे मटके में उगाया जा सकता है। बुआई के बाद मिट्टी से ढ़ककर उसके ऊपर 2सब्जी बगीचा का मुखय उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तथा वर्ष भर घरेलू साग-सब्जी की आवश्यकता की पूर्ति करना है। बगीचा के एक छोर पर बारहमासी पौधों को उगाया जाना चाहिए जिससे इनकी छाया अन्य फसलों पर न पड़े तथा अन्य साग-सब्जी फसलों को पोषण दे सकें। बगीचा के चारों ओर तथा आने-जाने के रास्ते का उपयोग विभिन्न अल्पावधि हरी साग-सब्जी जैसे - धनिया, पालक, मेथी,पुदीना आदि उगाने के लिए किया जा सकता है।

50 ग्राम नीम के फली का पाउडर बनाकर छिड़काव किया जाता है ताकि इसे चीटियों से बचाया जा सके। टमाटर,गोभी, बैगन, मिर्ची के लिए 25-30 दिनों की बुआई के बाद तथा प्याज के लिए 40-45 दिनों के बाद पौधे को नर्सरी से निकाल दिया जाता है।टमाटर, बैंगन और मिर्ची को 30-45 सेंमी की दूरी पर मेड़ या उससे सटाकर रोपाई की जाती है। प्याज के लिए मेड़ के दोनों ओर रोपाई की जाती है। रोपण के बाद पौधों की सिंचाई की जाती है।

प्रारंभिक अवस्था में इस प्रतिरोपण को तीन -चार दिन बाद पानी दिया जाए तथा बाद में 6-7 दिनों के बाद पानी दिया जाए।

सब्जी बगीचा का मुखय उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तथा वर्ष भर घरेलू साग-सब्जी की आवश्यकता की पूर्ति करना है। बगीचा के एक छोर पर बारहमासी पौधों को उगाया जाना चाहिए जिससे इनकी छाया अन्य फसलों पर न पड़े तथा अन्य साग-सब्जी फसलों को पोषण दे सकें। बगीचा के चारों ओर तथा आने-जाने के रास्ते का उपयोग विभिन्न अल्पावधि हरी साग-सब्जी जैसे - धनिया, पालक, मेथी,पुदीना आदि उगाने के लिए किया जा सकता है।

फसल चक्र

वर्षा, शरद और ग्रीष्म की फसलें तालिका में बतलाए अनुसार लेना चाहिए -

वर्ष भर उगाने के लिए फसल चक्र

खरीफ	रबी	जायद	खरीफ	रबी	जायद
पालक	मिर्च	ककडी	बैंगन	मूली	भिण्डी
तरोई	लहसून	छप्पन कद्दू	लोबिया	आलू	कद्दू
टमाटर	मैथी	तरबूज	मूली	प्याज	धनिया
टिण्डा	मटर	टमाटर	प्याज	पालक	करेला
भिण्डी	पत्तागोभी	करेला	भिण्डी	मूली	तरोई
लौकी	आलू	खरबूज	धनिया	फूलगोभी	लौकी
फूलगोभी	धनिया	प्याज	पुदीना	पुदीना	पुदीना
मिर्च	बाकला	टिण्डा	केला	केला	केला
ग्वार	बैंगन	बैंगन	नींबू	नींबू	नींबू
मिर्च	गाजर	पालक	पपीता	पपीता	पपीता

बारहमासी खेत

सहजन की फली, केला, पपीता, कढ़ी पता उपरोक्त फसल व्यवस्था से यह पता चलता है कि वर्षभर बिना अंतराल के प्रत्येक खेत में कोई न कोई फसल अवश्य उगाई जा सकती है। साथ ही, कुछ क्यारियों में एकसाथ दो फसलें (एक लम्बी अवधि वाली और दूसरी कम अवधि वाली) भी उगाई जा सकती है।

सब्जी बगीचा निर्माण के आर्थिक लाभ

व्यक्ति पहले अपने परिवार का पोषण करता उसके बाद बेचता है। आवश्यकता से अधिक होने पर उत्पाद को बाजार में बेच देता है या उसके बदले दूसरी सामग्री प्राप्त कर लेता है। कुछ मामले में घरेलू बगीचा आय सृजन का प्राथमिक उद्देश्य बन सकता है। अन्य मामले में, यह आय सृजन उद्देश्य के बजाय पारिवारिक सदस्यों के पोषण लक्ष्य को पूरी करने में मदद करता है। इस तरह, यह आय सृजन और पोषाहार का दोहरा लाभ प्रदान करता है।

चना

चना मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। प्रदेश में देशी, काबुली और गुलाबी चना की फसल सफलतापूर्वक ली जाती है। प्रदेश में लगभग 28.50 लाख हेक्टेयर में चने की फसल ली जाती है तथा उत्पादन लगभग 24.76 लाख टन है। इस प्रकार मध्यप्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक चना उत्पादन वाला प्रदेश है। प्रदेश की औसत उपज लगभग 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। चना उत्पादन की उन्नत तकनीक को अपनाना आवश्यक है।

भूमि का चुनाव एवं खेत की तैयारी – चना फसल के लिए सबसे उपयुक्त मध्यम से भारी भूमि होती है। भूमि का पी.एच.मान 5.6 से 8.6 के बीच होता होना चाहिए। हल्की भूमि में चना फसल लेने की बाध्यता होने पर उसमें गोबर की खाद या हरी खाद का आवश्यक रूप से उपयोग करना चाहिए जिससे भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाए। जिन खेतों में खरीफ फसल नहीं ली गई हो दो बाद आड़ा एवं खड़ा बखर चलाकर नमी को संरक्षित करें। जहां खरीफ फसल ली गई है वहां फसल की कटाई के तुरंत बाद पहले दिन एक बखर चलाकर दूसरे दिन उसके विपरीत दिशा में दूसरी बार पाटा सहित बखर चलाएं और खेत को बोने के लिए तैयार करें। खरीफ फसलों के अवशेषों को खेत से बाहर निकालें।

उन्नत किस्में – चने की उन्नत किस्मों का चुनाव भूमि के प्रकार सिंचाई जल की उपलब्धता व पिछ्ले वर्षो में रोगों के प्रकोप की स्थिति आदि को ध्यान में रखकर ही करें। विभिन्न जातियों का प्रमाणित बीज ही उपयोग करें। चने की संस्तुत किस्मों का विवरण तालिका में दिया गया है।

बीज की मात्रा एवं बीजोपचार – चने की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए पौधों की संख्या तीन से साढ़े तीन लाख / हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके लिए प्रति वर्गमीटर 30 से 35 पौधे होना चाहिये। सामान्य रूप से इस पौध संख्या को प्राप्त करने के लिए 75 से 100 किलोग्राम बीज / हेक्टेयर की आवश्यकता किस्मों के बीज आकार के अनुसार होती है। कतारों से कतारों की दूरी 30 से.मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से.मी. रखकर वांछित पौध संख्या प्राप्त की जा सकती है।

बुवाई के पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें। थायरम 2 ग्राम तथा कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम तथा पीएचबी कल्चर से 5 ग्राम प्रत्येक को प्रति किलो ग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें और उपचारित बीज को छाया में सुखाकर बोआई करें। राइजोबियम कल्चर जे.पी.एस 65 का उपयोग लाभप्रद पाया गया है।

बोने का समय– सामान्य बोनी का समय 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक है। सिंचित खेती के लिए नवंबर अन्त तक बोआई कर सकते हैं। देर से बोनी की स्थिति में उपयुक्त जाति का चयन करें तथा दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बोनी करें।

खाद एवं उर्वरक – मिटटी परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। चने की फसल को सामान्यत~ 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन , 45 ङ्क 50 किलो ग्राम स्फुर 20 किलोग्राम पौटाश की आवश्यकता होती है। सिंचिंत फसल में उपरोक्त नत्रजन एंव पोटाश के साथ स्फुर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर दें। देर से बोई गई चने की फसल में नत्रजन 40 किलोग्रमा प्रति हेक्टर की दर से दें। जीवाणु खाद राइजोबियम तथा पी.एच.बी. के साथ 2.5 टन प्रति हेक्टर कम्पोस्ट खाद का उपयोग लाभप्रद होता है।

असिंचित खेती में लाभदायक उपाय– चने की असिंचित खेती में नमी की कमी ही मुख्य समस्या होती है। इससे अंकुरण कम हो सकता है तथा पौधों की बढ़वार और बीज के आकार में कमी होने से उपज कम हो जाती है। इससे बचने के लिए बोआई के

पूर्व बखर, पाटा चलाकर नमी संरक्षित करें। वर्षा होने या सिंचाई देने के बाद हेण्ड हो आवश्य चलायें इससे नमी एवं खरपतवार संरक्षण होगा।

सिंचाई – चने की फसल के लिए सामान्यरूप से दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के पहले बुवाई के लगभग 40 ङ्क 50 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई घेंटियों में दाना भरते समय बुवाई के 60 - 65 दिन बाद करना चाहिए। यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो उसे फूल आने के पहले दें। अधिक सिंचाई करने से पौधों की बढ़वार अधिक होती है और उपज में कमी आती है। फब्बारा विधि से सिंचाई करें। बहाव विधि से सिंचाई करने पर खेत को छोटी क्यारियों में बांट कर सिंचाई करें। इसके लिए बुवाई के तुरन्त बाद खेत में नालियां बना देना चाहिए।

अन्तर्वर्तीय फसलें – चने में अलसी और गेहूं को अन्तर्वर्तीय फसल के रूप में सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। चना की चार कतारों के बाद अलसी या गेहूं की दो कतार के हिसाब से बुवाई अधिक लाभप्रद होती है।

खरपतवार नियंत्रण – असिंचित खेती में खरपतवार कम आते है फिर भी बुवाई के लगभग एक माह बाद हेण्ड हो चलाएं जिससे खरपतवार नियंत्रतण होगा और नमी भी संरक्षित होगी। सिंचिंत फसल में नींदा नियंत्रण के लिए पेन्डिमिथलीन 1 लीटर प्रति हेक्टर 500 – 600 लीटर पानी मिलाकर अंकुरण पूर्व फलैट फेन नोजल से छिड़काव करें।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।